मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 14 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 2 – 8 अप्रैल 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

एक अकादमिक कसरत या हिन्दूराज कायम करने का अभियान.....3

वित्तीय संकट और इसके प्रभाव...5

अडानी के कारनामों पर जेपीसी जांच से क्यों घबराती है मोदी सरकार?.....7

14 अप्रैल से 15 मई 2023 तक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान

भाजपा हराओ–देश एवं जनता को बचाओ

डी. राजा

1925 में जब से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, पार्टी एक बेहतर जीवन के लिए जनता के संघर्षों की अगली कतार में रही है। देश और जनता के लिए बलिदान करने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अन्य किसी से पीछे नहीं रही है। हमारे शानदार इतिहास में हमारी पार्टी ने समाज के शोषित, हाशिए पर पड़े और भेदभावग्रस्त तबकों को आवाज दी है। पार्टी ने राष्ट्रीय एजेंडे के सकारात्मक दिशा में निर्माण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमारे संघर्षों का नतीजा समाज के हर तबकों के लिए भारी कामयाबियों के रूप में निकला है। जब हम अत्यंत मेहनत के साथ हासिल किए गए मजदूरों या किसानों को प्राप्त अधिकारों की बात करते हैं तो इनके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान अविस्मरणीय है। हमारा इतिहास सचमुच प्रेरणाप्रद है और जनता और समाज के लिए हमारे जिन शहीदों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया उनके खून से सम्पन्न है।

वर्तमान समय में हम देश में एक नयी एवं अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां हमारे देश के लोकतंत्र के अस्तित्व मात्र पर ही एक प्रश्नचिन्ह लगा है। आरएसएस के फूटपरस्त एजेंडे से नियंत्रित एक सरकार केन्द्र में और कई राज्यों में सत्ता में है। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जिन मूल्यों के लिए लड़ा गया, यह विचारधारा उन तमाम मूल्यों को खत्म कर रही है। जब से आरएसएस प्रायोजित हिन्दुत्व के नेरेटिव ने हमारे देश को ग्रस्त कर लिया है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के हमारे गणतंत्र के मुख्य मूल्यों को कुचला जा रहा है। मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत जातीय अत्याचार बढ़ रहे हैं और ऐतिहासिक तौर पर हाशिए पर पड़े तबकों के साथ भेदभाव ने संस्थागत रूप ले लिया है। क्रोनी पूंजीवाद हमारे देश के अमूल्य संसाधनों को खा रहा है और इसे सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है।

इस परिदृश्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने ने 14 अप्रैल से 15 मई 2023 तक जिस राजनीतिक अभियान का आह्वान किया है वह जनता के ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अक्टूबर 2022 में विजयवाड़ा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव ने ''जनस्वास्थ्य, जनशिक्षा, भूमि, आवासन, रोजगार और खाद्य सुरक्षा को हमारे एजेंडे की मूलभूत मांगों के तौर पर '' चिन्हित किया है। अपने राजनीतिक अभियान के दौरान हमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की विफलता को रेखांकित करना चाहिए। हमें इन मांगों को जनता के सामने कारगर तरीके से रखना चाहिए और इनके लिए जनता को लामबंद करना चाहिए।

14 अप्रैल डा. अम्बेडकर की जन्म जयंती है जो हमारे संविधान के मूख्य निर्माता थे और जिन्होंने जीवन भर सामाजिक न्याय और जातीय भेदभाव के खात्मे के लिए संघर्ष किया। 1 मई का दिन दुनिया भर के मजदूरों द्वारा मनाया जाना वाला दिन है। हमारी पार्टी को सामाजिक न्याय और समाजवाद के लिए जनता को लामबंद करना चाहिए और इन उद्देश्यों का जनता के बीच में प्रचार करना चाहिए।

हमारे अभियान में उन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाया जाना चाहिए जो हाल में सामने आये हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के गलत कारनामों और धोखाधड़ी के संबंध में हिंडनवर्ग रिपोर्ट ने एक भूचाल पैदा कर दिया है और इस रिपोर्ट से मोदी सरकार का क्रोनीवाद सामने आया है। सरकार अनियमितताओं की जांच के लिए एक संसदीय कमेटी के गठन से इन्कार कर रही है जो स्वयं में उसकी मिलीभगत का सबूत है। आज संसद में विभिन्न पार्टियों के सदस्यों की संख्या जिस तरह की है, उसमें संयुक्त संसदीय समिति में भाजपा के सदस्यों का बहुमत ही रहेगा। तो भी सरकार इस मामले की संसदीय समिति द्वारा जांच से डरी हुई है। इससे साफ इशारा मिलता है कि मामले की जांच होने पर भाजपा के क्रोनी पूंजीवाद की अनेक बातें उजागर हो सकती हैं। हमारे अभियान के दौरान इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाना चाहिए।

इस मुद्दे का एक अन्य पहलू यह है कि देश में सरकार के शीर्ष स्तर पर व्यापक एवं संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे देश के लोगों के श्रम और योगदान से बनी राष्ट्रीय सम्पत्तियों को चंद चुनिन्दा लोगों को औने–पौने दामों में बेचा जा रहा है जबकि चुनावी बॉडों के जरिए भाजपा पैसे बना रही है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इसका लोगों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्रोनी पूंजीपतियों को उनके निवेश के कारण जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक जैसे संगठनों की समय–परीक्षित वित्तीय निष्ठा एवं स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इन संस्थानों में देश की जनता का पैसा लगा है। इस पैसे को जनहित के लिए इस्तेमाल करने के बजाय चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इन पूंजीपतियों के साथ भाजपा का गठजोड़ है। जनता की मेहनत की कमाई भ्रष्ट पूंजीपतियों की तिजोरी में पहुंच रही है जबकि देश के आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। देश के आम लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है। हमारे अभियान के दौरान इन तमाम बातों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए, सरकार के इन कामों के खिलाफ जनता को एकताबद्ध किया जाना चाहिए।

भाजपा चुनावी तरीके के जरिए सत्ता में आई, परन्तु इसकी विचारधारा का स्रोत आरएसएस अपने जन्म से ही लोकतंत्र विरोधी है। आरएसएस विचारधारा के अंतर्गत सरकार स्वयं इस तरह के कामकाज कर रही है जो अपनी प्रकृति में अलोकतांत्रिक है। सरकार अलोकतांत्रिक तौरतरीकों को बढ़ावा दे रही है। जनता के नागरिक अधिकारों का नियमित तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है और हमारे गणतंत्र के संवैधानिक ढांचे के साथ नियमित तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। संसदीय बहुमत का दुरूपयोग कर संसद को बेकार की चीज बनाया जा रहा है और हरेक विरोध को राष्ट्रविरोधी करार कर दिया जाता है। मीडिया को इतना दबा दिया गया है कि वह सरकार की हां में हां मिलाता है; सरकार की लाइन पर चलता है और विपक्ष को बदनाम करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका द्वारा लगातार चुनौती दी जा रही है। हमारे राजनीतिक अभियान के दौरान पार्टी को इन मुद्दों को जनता तक ले जाना चाहिए और क्रोनी–हिंदुत्व ताकतों के हमले से देश को बचाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक ताकतों को एकताबद्ध करने की अपील करनी चाहिए।

कांग्रेस संसद सदस्य राहुल गांधी को एक मामले में सजा दिए जाने और उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म किए जाने से लोकतंत्र का भविष्य, असहमति/विरोध की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थानों के अस्तित्व के संबंध में अनेक सवाल पैदा हो गए हैं। इससे विपक्ष को डराने–धमकाने और एक तानाशाही फासिस्टी शासन स्थापित करने की भाजपा–आरएसएस की कुटिल साजिश का संकेत मिलता है।

इन एवं अन्य अनेक मुद्दों पर हमारा राजनैतिक अभियान अनेक तरीके से किया जा सकता है जिसमें प्राथमिक तौर पर सभी जिलों में पदयात्रा करना शामिल है। आरएसएस–भाजपा शासन के कारनामों का पर्दाफाश करने वाले और अपने एजेंडे को सामने लाने वाले पर्चे–पोस्टर सभी भाषाओं में छपवाए जाने चाहिएं और जनता के बीच बांटे जाने चाहिएं। जनता के बीच, खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपने वर्ग संगठनों, जनसंगठनों और सांस्कृतिक मोर्चो के साथ तालमेल कर साम्प्रदायिक भाईचारे, साझा इतिहास और हर किस्म की फूटपरस्ती के खिलाफ समाज को एकजूट करने की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाने चाहिएं। सभी धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक ताकतों के साथ सिद्धांतगत एवं विचारधारात्मक एकता के निर्माण पर हमारे अभियान के दौरान खासतौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि यह केवल वामपंथ ही है जो विचारधारात्मक तौर पर आरएसएस–भाजपा को चुनौती दे सकता है और एक जनता–परस्त विकल्प जनता के सामने पेश कर सकता है। हमारे राजनैतिक अभियान में इस बात को जनता के सामने सफलतापूर्वक ले जाया जाना चाहिए।

2024 में लोकसभा का चुनाव हमारे देश के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक राज्य विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कर्नाटक के लोग 10 मई 2023 को मतदान करने वाले हैं। कर्नाटक को भाजपा के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वारा समझा जाता है। देश और संविधान को बचाने के लिए इन चुनावों में भाजपा को हराये जाने की जरूरत है।

संघर्ष और बलिदानों के हमारे गौरवपूर्ण इतिहास ने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें एक अभिन्न अंग बनाया है। इस नाजुक समय में वामपंथ की यह एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि अपने देश, अपने संविधान को आरएसएस–भाजपा की फूटपरस्त एवं शोषक व्यवस्था से जो खतरा पैदा हो गया है, वामपंथ उसके खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करे। लाल झंडा हमेशा आम आदमी के साथ खड़ा हुआ है। यदि हम एक वैकल्पिक एजेंडे के साथ देश की जनता के पास पहुंचते हैं तो हमारा राजनैतिक अभियान सफल होगा।

समय का तकाजा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत बने। आइए, सांप्रदायिक, फासिस्ट ताकतों की चुनौतियों का सामने करने के लिए हम संघर्ष करें और पार्टी को मजबूत करें।

जनवादी मूल्यों का उल्लंघन

संपादकीय

जब संकट के घने काले साये में सबकुछ गुम होने लगता है, विनाश के कदमों तले सारी जनता तड़पने लगती है, सिवाय सबसे ऊंचाई पर बैठे कुछ लोगों के, तो वह क्षण आता है जब दक्षिणपंथी ताक़तों का वर्चस्व पूरी व्यवस्था पर काबिज़ हो जाता है। छोटे, मझोले और लघु उद्योगों (एमएसएमई) को छोड़ कर, चोटी पर बैठे देश का सबसे धनी हिस्सा अपने स्वार्थ की पूर्ति के रास्ते ढूंढता रहता है। इस कोशिश में दक्षिणपंथी ताक़तों का व्यवस्था पर काबिज़ होना भी आसान हो जाता है। इस सबके साथ ही बुनियादी संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का पूरा बोझ उठाती रहती है समाज के सबसे नीचे कोने में रहने वाली गरीब जनता, जो उत्पादन भी करती है और उत्पादन के साधनों का विकास करने में भी मदद करती है, लेकिन ये मज़दूर वो है जिनके पास रोज़गार है, और सोलह से अठारह घंटों का कठिन श्रम उन्हें जीवित से अधिक मृतप्राय ही छोड़ता है। जहां तक आम जनता का सवाल है, वे भूख के ही साम्राज्य में रहते हैं। इसलिये विश्व स्तर पर भूख पर सर्वे के परिणामों में 121 देशों में हम 106वें स्थान पर हैं। औपचारिक रोज़गारों की संभावनाएं घटकर 7.5 प्रतिशत रह गई है। यह पिछले दो दशकों से भी कम है। ई.पी.एफ. के ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण रोज़गारों में 7.7 की गिरावट दर्ज हुई है। सी.एम.आई.ई.ए. कहती है कि गिरावट का अधिकतम हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में में है, और यह भी कि गैर–कृषि संबंधित क्षेत्रों से है। इसका भयानक प्रभाव दिहाड़ी मज़दूरों की स्थिति पर सबसे अधिक पड़ा है और वे घटकर सिर्फ करीब पंद्रह मिलियन रह गए है।

क्रमशः जनवादी संरचना को तोड़ने की कोशिश चल रही है ताकि दक्षिणपंथ सत्ता में आ सके। देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था वहां पहुंच चुकी है जहां से सुधार की संभावना कठिन है। विश्व आर्थिक संकट के बाद के दशक में बैंकिंग में भी बनावट में गहराई से परिवर्तन लाने की कोशिश जारी है। बहुत अधिक मात्रा में कर्ज देना, बिना समुचित पूंजी और पैसे के ख़तरनाक क़दम उठाना, ये सब वित्तीय स्थिरता और उसके विकास को ख़तरे में डालती हैं। संकट के कारण बैंकों के विकास की पूरी संभावना ख़त्म हो चुकी है और अमानवीय रूप से यह क्षेत्र घटता जा रहा है। संकट के बहुत सारे आयाम होते हैं। व्यवस्था को बचाने के लिये प्रमुख क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनमें बैंक भी शामिल हैं। अब यह सारा कुछ उल्टी दिशा में हो रहा है, कई क्षेत्रों का निजीकरण हो चुका है और कुछ अभी भी अपवाद है। मार्च 29,2023 को सरकार ने 106 कोयले की ख़दानों को व्यावसायिक नीलामी के सातवें चरण में डाला है। सरकार हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड या, हॉल के भी 3.5 प्रतिशत को प्रति शेयर 2450 रुपयों की दर से दांव पर लगा चुकी है। इस सबकी लाभ राशि निजीकरण से प्राप्त राशि में जुड़ जायगी। सरकार अब हॉल के 75 प्रतिशत शेयर पर कब्ज़ा कर चुकी है। हॉल केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगों में से है जो डिफेन्स मंत्रालय के अधीन है। पिछले महीने सरकार ने विनिवेश की प्राप्ति और स्थिति के कमतर आंकड़े पेश किए थे जो बजट के टारगेट में 65,000 करोड़ रुपए हैं। उसकी जगह यह विनिवेश मात्र 50,000 करोड़ का ही है। इस बीच सरकार ने विनिवेश और शेयर की वापस खरीदी से 31,106,14 करोड़ का धन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों से उठा लिए थे।

यह स्पष्ट हो चुका है कि पूरे कर्ज की कीमत विशाल जनता की खून–पसीने की कमाई से चुकाई जाएगी। बदले में उन्हें मिलेगी बेरोज़गारी, शोषण और उत्पीड़न। उन्हें बांटने वाली ताक़तें भी आज सक्रिय हैं। समाज जाति और समुदाय के आधार पर टुकड़ों में बंट रहा है। बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों की कीमत पर उत्साहित किया जा रहा है बिखराव को तेज करने के लिये। शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय और रोज़गार की समस्याओं को पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है। आज मजदूर और किसानों में एकता हो रही है और वे संगठित हो रहे हैं, और यह सब सत्ता में जो दक्षिणपंथी ताक़तें हैं, उनके स्वार्थ के विरूद्ध है। उन्हें मूक, स्तब्ध आत्मसमर्पण ही चाहिये होता है? जो उन्हें जंजीरों में जकड़ी जनता से मिलता ही रहा है। यह सब दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताक़तों के सत्ता में आने का रास्ता ही सरल बनाने में सहायता करते हैं। यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमें अधिकाधित संगठित होना है। लेकिन हमारी हर ऐसी कोशिश से सत्तापक्ष में एक भय का ही संचार होता है, जो उनकी कमज़ोरी को उजागर करता है।

वे समाज के सभी तबकों, समुदायों की बढ़ती हुई एकता से घबराए हुए हैं और इसलिये संसद की कार्यवाही को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह वही जगह है जहां उनसे सवाल किया जाता है, और जवाब की उम्मीद की जाती है, हर अन्याय, अपराध पर उनकी कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है। वे इस बात से भी डरे हुए है कि जनता क्रमशः इस सत्य के प्रति सचेतन हो रही है कि शोषित जनता को एकता से ही मुक्ति मिल सकती है और इसके लिये संघर्षों की शुरूआत भी हो सकती है। वे उन सब अन्यायों, जकड़नों का जवाब मांग सकते हैं जो सत्ता पक्ष लगातार उनके खिलाफ चलाती रही है। इस गहरे अंधकार को दूर करने की हर कोशिश को प्रतिक्रियावादी ताक़तें कुचलने में लगी रहती हैं। वे अपनी ही दुर्बलताओं से डरे रहते हैं और इसलिये अपनी सत्ता जमाये रखने में उन्हें अत्याचार का जोर लगाना पड़ता है।

जब दक्षिणपंथी ताक़तें भंयकर रूप धारण करती हैं, तो उनका उद्देश्य मेहनतकशों को निरंतर भयभीत रखना होता है। उन्हें इन तबकों का उठ खड़ा होना और दमित होने का सबल विरोध करना स्वीकार नहीं है। इसलिये सत्ता पक्ष चाहता है कि धरती बंजर ही रहे, उनके पैरों तले दबी–कुचली हुई। वे नहीं चाहते कि उसकी छाती पर विरोध की हरी–भरी कोंपल उगे। वे अंधी आज्ञाकारिता चाहते हैं और इसी निषेधात्मकता के साथ वे पूरी इंसानियत पर काबू पाना चाहते हैं, और हर बार अपनी इस कोशिश में उन्हें हार ही मिलती है। इस सबमें सिर्फ तीखा प्रतिशोध बच जाता है, जो संपूर्ण जनता के विरूद्ध होता है, जो मेहनतकश हैं, मजदूर और किसान हैं और साथ ही क्रांतिकारी हिस्सा हैं किसान, मज़दूर और प्रबुद्ध वर्ग के ।

यह दक्षिणपंथी ताक़तों का असली चेहरा है, जो पूंजीवाद को उसके अंतिम चरण तक पहुंचाता है, अर्थात वित्तपूंजी तक, जो पूरी आर्थिक व्यवस्था को काबू में कर लेता है। बहुत सारे देशों में, दक्षिणपंथी ताकतों ने सामाजिक भाषणों से जनता की मानसिकता पर कब्जा किया है, इस संकट की घड़ी में सर्वहारा तक का एक हिस्सा इसमें दिशाहीन हो जाता है। इन सारे तबकों ने कभी भी दक्षिणपंथी ताक़तों से समझौता नहीं किया होता अगर उन्हें इनका सही चेहरा–सही चरित्र समझ में आ गया होता!

एनएफआईडब्ल्यू की केरल के भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की अध्यक्ष अरुणा रॉय और महासचिव एनी राजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 मार्च, 2023 को लिखे गए पत्र का पाठ इस प्रकार है, जिसमें भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के द्वारा भाकपा (मा) की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है:

हम, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू), महिलाओं के अपमान के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को आपके संज्ञान में लाने के लिए यह लिख रहे हैं और यह भाजपा के केरल राज्य अध्यक्ष के सुरेंद्रन द्वारा किया गया कृत्य है।

26 मार्च, 2023 को जी–20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में स्त्री शक्ति सम्मेलन के लिए एक स्वागत समिति गठित करने के उद्देश्य से केरल के त्रिशूर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सुरेंद्रन ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

सभा को संबोधित करते हुए, सुरेंद्रन ने कहा: 'कम्युनिस्ट पार्टी की महिला नेता पैसा लूट कर मोटी हो गई हैं' और 'पूतना की तरह मोटी होकर, वे केरल की महिलाओं का अपमान कर रही हैं।

एनएफआईडब्ल्यू की राय में यह टिप्पणियां यौन, रंग हैं, बॉडी शोमिंग करने और महिलाओं की गरिमा का अपमान करने वाली हैं और जिसका संबंध केवल उन लोगों पर हमले के रूप में नहीं जो किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंधित हैं, बल्कि यह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। सुरेंद्रन के महिला विरोधी बयानों की हम निंदा करते हैं।

हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरेंद्रन के शब्द हमारे देश की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे जो अब से कुछ महीनों में जी–20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। आप भारत के प्रधानमंत्री और जी–20 के वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते, हम आपसे सुरेंद्रन के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करते हैं।

भाकपा सांसद सार्वजनिक उपक्रम समिति के लिए चुने गए

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय समूह के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सचिव बिनॉय विश्वम को सार्वजनिक उपक्रम समिति के लिए चुना गया। हालांकि वामपंथी संख्या में संसद में एक बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन बिनॉय विस्वाम चुने गए।

अपने सभी साथी सांसदों को धन्यवाद देते हुए बिनॉय विश्वम ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में यह जीत उल्लेखनीय है। कि धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, वाम ताकतें लड़कर जीत सकती हैं।

भाकपा ने सांसदों को हिरासत में लेने और राहुल गांधी को अयोग्य ठहराये जाने की निन्दा की

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 24 मार्च 2023 को निम्नलिखित बयान जारी किया:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षी दलों से जुड़े संसद सदस्यों को हिरासत में लिये जाने की निंदा करती है जो कई मुद्दों को लेकर भारत के राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में दिल्ली पुलिस द्वारा भाकपा के पी. संदोष कुमार सहित विपक्ष के प्रमुख नेताओं और अन्य को हिरासत में लेना निंदनीय है।

कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की दोषसिद्धि और अयोग्यता के मामले तेजी ने लोकतंत्र के भविष्य, असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। अडानी कांड पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग को पूरी तरह से नकार कर भाजपा–आरएसएस शासन संसद को बेमानी बना रहा है और लोकतंत्र को कुचल रहा है।

आज देश के बिगड़ते हालात सभी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी ताकतों और लोगों के संयुक्त संघर्ष और देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा–आरएसएस को सत्ता से हटाये जाने की की मांग करते हैं।

एक अकादमिक कसरत या हिन्दूराज कायम करने का अभियान

प्रो. अरूण कुमार

दुनिया के विकास के साथ इतिहास के अध्ययन, खोज और बहस के प्रति रुचि गहरी होती गयी है और बहस बढ़ती रही है। भारत में भी इतिहास के प्रति यही रुझान रहा है। लेकिन आजकल, खासकर केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इतिहास पर बहस और इसके पुनर्लेखन पर सरकार सहित समाज के खास वर्ग का रुख आक्रमक हो चला है। इतिहास के प्रति सरकार और उनके कुनबे का यह रवैया अकारण नहीं है और इसे देश के वर्तमान संदर्भ और राजनीतिक प्रक्रिया से अलग करके देखा भी नहीं जा सकता। इसका विश्लेषण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की समग्रता में ही संभव है और उचित भी।

नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के दौर में इतिहास का विषय कारपोरेट और कट्टरपंथी शक्तियों के बीच सेंडविच बना हुआ है। बाजार की दृष्टि और कारपोरेट की दुनिया में इतिहास अप्रांसगिक है। लेकिन कट्टरपंथियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है। वे वर्तमान इतिहास पर अनेक सवाल खड़ा कर और नई–नई बातों की चर्चा छेड़कर इतिहास के तथ्यों को बदलने, झुठलाने और भ्रमित करने का अभियान चलाकर अपने सैद्धांतिक आधार को विस्तार देने का लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति पर चलने वाली वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कारपोरेट और कट्टरपंथियों के बीच बढ़िया तालमेल देखने को मिल रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण नेता/कार्यकर्ता तक इतिहास के पुनर्लेखन और इसमें बदलाव के प्रति काफी आक्रमक तर्क और रुख दिखा रहा है। केन्द्र सरकार वे सारे कार्य कर रही है और तमाम कदम लगातार उठा रही है जिससे इतिहास के तथ्यों को बदला/पलटा जा सके ताकि युवा पीढ़ी का ब्रेनवाश हो सके साथ ही उनके कट्टरपंथी विचारों को सामाजिक स्तर पर जरुरी विस्तार मिल सके। उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन का आधार संपुष्ट हो सके। इतिहास में नये विरोधाभासों को खड़ा कर अपने दर्शन और विचार के अनुकूल उसे ढालना चाहते हैं। बड़ी ही निर्लज्जता से वे तथ्यहीन और गैर जरूरी अनेक सवालों पर बेझिझक बहस छेड़ रहे हैं। इतिहास के पुनर्लेखन के पक्ष में उनके क्या तर्क हैं? किन प्रश्नों को सामने कर वे इतिहास के पुनर्लेखन और बदलाव पर जोर देते हैं?

इतिहास लेखन आसान नहीं है। बहुत कठिन है। यह न कोई किस्सा–कहानी नहीं और न ही किसी कवि की कल्पना का इजहार है। इतिहास किसी राजनीतिक उंचाई प्राप्त करने की सीढ़ी भी नहीं है। इतिहास वस्तुतः इतिहासकार और समकालीन वास्तविकताओं के बीच के अंतर्संबंधों की तथ्यात्मक अभिव्यक्ति है। इतिहास भूत और वर्तमान के बीच का संवाद है। इतिहास की प्रकृति और चरित्र वैज्ञानिक, समावेशी और उद्देश्यपूर्ण होता है। इतिहास लेखन तथ्यों के आधार पर होता है। यह किसी मिथक या उपन्यासिक कल्पना पर आधारित नहीं होता। इतिहासकार का कर्तव्य होता है कि वे सत्य की खोज करें। इतिहासकार हमेशा विस्तृत दायरे में अपनी खोज और तथ्यों को संवैधानिक मूल्यों और नीतियों की कसौटी पर कसते हैं। इतिहास का निष्कर्ष कभी एक पक्षी और स्थूल नहीं होता है। जब भी कोई नये तथ्य सामने आते हैं उस आधार पर इतिहास के निष्कर्ष बदलते हैं।

फिर इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर इतना अंतर्विरोध और हाय तोबा देश में क्यों मचा है?

इतिहास लेखन एक अकादमिक कार्य है जो इसका निष्कर्ष वैज्ञानिक मानकों और खोजबीन पर आधारित होता है साथ ही उसकी समझ उद्देश्य पूर्ण होता है। इतिहास लेखन इतिहास की समझ और ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला होता है। फिर आजकल इस विषय को लेकर इतना हो हल्ला क्यों है?

वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षानीति–2020 में भी इतिहास के प्रति सरकारी रुझान स्पष्ट है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा गायब कर दी गयी है। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास और हिन्दू राजाओं की गौरव गाथाओं को काफी विस्तार से अंकित किया गया है। इसी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षो के इतिहास को नजर अंदाज करने की कोशिश की गई है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत जिन मूल्यों और आदर्शो को लेकर आगे बढ़ा उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। ये अकारण नहीं है? इसके निहितार्थ हैं। उपनिवेशवाद और भारत की आजादी के लम्बे संघर्षो में आज सत्ता में बैठे और उसके पोषण में तल्लीन जमातों का योगदान शून्य रहा है। ब्रिटिश राज के तलवे सहलाने और हिन्दू –मुस्लिम में भारतीय समाज को बांटने में अगुआ रहे हैं। इतिहास का पुनर्लेखन अपने इस कलंक को मिटाने की मंशा से भी वे चाहते हैं और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के मूल भावना को संपुष्ट करने के लिए भी।

यह तथाकथित इतिहास स्कूलों के पाठ्यक्रमों के कुछ भागों को जैसे तैसे विलोपित कर बदलने की कोशिश हो रही है। साथ ही अपने तरह की पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रमों में जबरदस्ती शामिल करके। इन पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में किसी नामी गिरामी इतिहासकारों और शिक्षाविदों की कोई राय भी नहीं ली गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टरपंथियों और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के पक्ष में दलील देने वाले लोगों को शामिल किया गया है। इसे पूरा करने के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, यूजीसी सहित केन्द्र और राज्यों में कार्यरत विभिन्न स्कूल बोर्ड को अभियान चलाकर पूरा करने का टास्क दिया गया है। और यह तेज गति से हो भी रहा है। सत्ता के दबाव में सभी संस्थाओं के स्वरूप को बदल दिया गया है। आई.सी.एच.आर. को उनके दर्शन के

इतिहास का पुनर्लेखन

अनुकूल शोध करने और प्रकाशन का निर्देश है। और वही हो भी रहा है। यह कोई नये इतिहास की खोज नहीं है, बल्कि अपने प्रोपेगंडा को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही आने पीढ़ियों में हिन्दू राष्ट्रवाद और मुस्लिम विरोधी मानसिकता स्थापित करना उनका मूल उद्देश्य है। इतिहास का हिन्दुवादी सिद्धांत गढ़ने से भारतीय इतिहास को 9वीं सदी के उपनिवेशवादी इतिहास होने की ओर धकेला जा रहा है। इसे नया और वास्तविक भारतीय इतिहास का अमली जामा पहनाने का नाटक जारी है। जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस पर अनेक सवाल उठाये हैं और अनेक आधुनिक इतिहासकारों ने इसे झूठ और बेतुका करार देकर नकार दिया है। इतिहास का नया संस्करण कट्टरपंथियों और उपनिवेशवादियों के इतिहास को स्थापित करने वाला है। हेडगेवार का विश्वास था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, जिसे उत्पीड़ित किया गया है और बार बार मुस्लिम वंशजों (दिल्ली सल्तनत और मुगलों) ने आक्रमक कर बर्बाद किया है। तब ब्रिटिश राज कायम हुआ। वीर सावरकर के कार्यो से प्रेरित होकर उन्होंने ने इस समझ को आगे बढ़ाया, जिनका मानना था कि मुगलों ने हिन्दूओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का लगातार प्रयास किया है। वे भारत को मुस्लिम राज्य बनाना चाहते थे। हेडगेवार ने उनकी क्षमता और देश को एकताबद्ध रखने के लिए इटली की फांसीवादी पार्टी और मुसोलिनी की भी खूब प्रशंसा की है। इसी से प्रभावित होकर हेडगेवार ने हिन्दुवाद को राष्ट्र निर्माण को आधार बनाया और यूरोप के फांसीवादियों से प्रभावित होकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की। उनकी समझ थी कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हिन्दुओं को मजबूत और एकताबद्ध होना जरूरी है। इसके लिए उनके पूर्वजों ने शहादत दी है, खून बहाया है। उनकी समझ थी कि यह धरती केवल हिन्दुओं की धरती है।

वर्तमान सरकार द्वारा इतिहास पुनर्लेखन के लिए गठित चौदह सदस्यीय समिति ने कहा है कि वे पुरातत्व साक्ष्यों के साथ साथ डीएनए टेस्ट करके साबित करेंगे कि इस धरती पर सबसे पहले हजारों साल पूर्व हिन्दुओं का अवतरण हुआ। जो भी पुरातात्विक प्रमाण और शिलालेख सच्चाई हैं। सरकार, उनके मंत्रियों, समिति के सदस्यों और सत्ता पोषण में लगे तमाम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन के अनुकूल हिन्दू राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के पक्ष में भारतीय इतिहास का प्रस्तुतीकरण किया जाय। वे आक्रमक तरीके से वे कर भी रहे हैं। अपने बहुमत और राजनीतिक शक्ति का खुलेआम दुरुपयोग कर भारत की पहचान हिन्दू राष्ट्र और भारत की धरती हिन्दुओं की धरती साबित करने पर आमादा हैं। वे भारत के बहु सांस्कृतिक स्वरुप को आधुनिक भारत को माइग्रेसन,इनवेशन और कन्वर्शन का परिणाम मानते हैं। देश की अठ्ठारह करोड़ मुस्लिम सहित पूरे एक सौतीस करोड आबादी को हिन्दू मानते हैं। मुसलमानों के अस्तित्व को नकारते हुए उन्हें भी मूल रुप से हिन्दु मानते हुए, भारत माता को स्वीकार करने का दबाव बनाते हैं।

विद्यालयों के साथ साथ विश्वविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों को जगह दी जा रही है। उनका मानना है कि मात्र तीन से चार हजार साल पहले मध्य एशिया के लोग भारत आये और उन्होंने भारत की आबादी को बदल दिया है। जबकि हिन्दू उनसे हजारों साल पहले आये। महान इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि हिन्दुओं के भारत में सबसे पहले पहले आने की बात कहकर वे भारत में हिन्दू नागरिकता का वर्चस्व साबित तो करना चाहते हैं, साथ ही हिन्दू धर्म आयातित नहीं है, यह भी बताना चाहते हैं। रामायण, महाभारत, और वेदों को ऐतिहासिक तथ्य बताकर वे अपने अपने को संपुष्ट कर रहे हैं और इतिहास को दिग्भ्रमित करने पर तुले हैं। बीजेपी के सभी लोग मुसलमानो को आक्रमणकारी मानते हैं। प्रो. राजपूत और प्रो. शरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक के समर्थक इतिहासकार सहित भाजपा के लोग मानते हैं कि वर्तमान इतिहास मुगलों के पक्ष में लिखा गया है और इसमें संतुलन होना जरूरी है। केवल ब्रिटिश राज के मात्र 200 सालों से प्रभावित होकर वर्तमान इतिहास लिखा गया है, जबकि पूर्व के इतिहास को जानबूझकर छोड़ दिया गया। इसे वे वामपंथियों और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की साजिश मानते हैं। उनकी योजना स्पष्ट है कि हिन्दुओं राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, विभिन्न चर्चित नायकों को महिमा मंडित कर इतिहास को लिखा जाये। एक राष्ट्रीय भावना का आभाषी एहसास कराकर और सांप्रदायिक माहौल तैयार कर अपनी सत्ता को और मजबूत करने की महायोजना बनायी जा रही है ताकि देश की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाना आसान हो जाये।

विदेशी जितने वंशजों ने भारत में राज किया, उसमें मुगल का सबसे ज्यादा समय (1526–1761) तक राज रहा। आज भी अकबर सबसे उदार, धर्मनिरपेक्ष और महान शासक माना जाता है। मुगलकालीन कलाकृतियां आज भी भारतीयों के साथ साथ विदेशी सैलानियों को सर्वाधिक पसंद है। मुगलों ने कई दृष्टिकोणों से भारत को समृद्ध किया है और उन्हें उपनिवेशवादी या आक्रमकारी नहीं माना जाता। एक एक कर मुगलकालीन चिन्हों को मिटाने का अभियान सरकार चला रही है। हाल ही में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम,जो ताजमहल के नजदीक है, का नाम हिन्दू राजा छत्रपति शिवाजी के नाम रखने का आदेश दिया है। शिवाजी हिन्दू राज कायम करने के लिए जाने जाते हैं जबकि आगरा मुगल शासक सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। योगी जी खुले आम कहते हैं कि मुगल हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं। मराठा शासक शिवाजी का नाम मुगल म्यूजियम से जोड़कर अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। यह भविष्य के भारत का एक बड़ा संकेत है। भाजपा का कहना है कि आगरा का ताजमहल हिन्दू शिवमन्दिर 'तेजो माहलया' पर बना है। इसे खूब

शेष पेज 14 पर...

अमरीकी बैंक संकट अनुत्पादक वित्त पूंजी का नकारात्मक प्रभाव

डा. सोमा मारला

हाल में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के कारण सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट सुइससे और अब जर्मनी बना एक प्रमुख क्रेडिट डयूश बैंक डूब गया है। अमेरिकी ट्रेजरी के हाल ही में ब्याज दर में वृद्धि के कारण यह बैंकिंग संकट खड़ा हुआ है। इस तरह से बैंकों के दुनिया भर में डूबने के भय के कारण अमेरिकी बैंक व्यवस्था में दरारें दिखाई दे रही हैं, जो कि अमरीका में 2008 में लेहमेन ब्रदर्स से उपजी आर्थिक मंदी की याद दिलाती हैं। इसका असर जल्दी ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

वर्तमान बैंकिंग संकट पिछले दशक के दौरान अनुत्पादक (वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए मुद्रा के अत्यधिक मुद्रण से) नकदी वित्त पूंजी के स्टॉक के कारण होता है। लोगों ने इस अतिरिक्त राशि को छोटे और मध्यम आकार के सिलिकॉन वैली जैसे बैंकों में जमा कर दिया। नतीजतन, अमेरिकी बैंकों में जमा राशि 13 ट्रिलियन से बढ़कर 18 ट्रिलियन हो गई। उत्पादक ऋणदाताओं की अनुपस्थिति में कम स्तर की मेनुफैक्चरिंग गतिविधि के अलावा छोटे और मध्यम आकार के बैंकों ने तेजी से स्टार्ट–अप्स, क्रिप्टोकरेंसी और खरीद का वित्तपोषण शुरू कर दिया। इस नगदी अतिरिक्त को बैंकों ने अमेरिकी फेडरल सिक्युरिटी बांड की बड़ी मात्रा खरीदने के लिए निवेश किया।

सरकारी खर्च और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक सरकारी बांड किसी सरकार द्वारा जारी की गई ऋण सुरक्षा है। फरवरी में उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरों में वृद्धि की। और इससे बॉन्ड का मूल्य कम हो गया। जैसे ही फेडरल फंड्स की ब्याज दरों में वृद्धि हुई सिलिकॉन वैली बैंक द्वारा धारित बांडों का बाजार मूल्य गिर गया, (यह अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक 25 बेसिस पॉइंट या 0.25 प्रतिशत पॉइंट पर बॉन्डों ने 1 बिलियन डॉलर खोए), इन फंड दरों को अब लगभग 450 बेसिस पॉइंट पर उठाया गया है। इसके परिसंपत्ति आधार में इस गिरावट के कारण बैंक पर 42 बिलियन डॉलर का संकट खड़ा हो गया, बैंकों के डूबने के डर से लोग बैंकों में जमा अपना धन निकालने के लिए दौड़े, अमरीकी राष्ट्रपति बीडेन के आश्वासनों के बावजूद संकट बढ़ता जा रहा है और अब यह संकट तेजी से यूरोपीय बैंकों को संक्रमित कर रहा है।

फेडरल बांड और अमेरिकी युद्ध उद्योग में वित्तीय निवेश के बीच एक जैविक संबंध है। हाल में फेडरल बांडों का तेजी से यूक्रेन युद्ध जैसे अन्य अमरीकी युद्धों में निवेश किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी बुलबुलों के फूटने, स्टार्ट–अप के डूबने और यूक्रेन युद्ध में अरबों डालर के लिए फेडरल बांड के इस्तेमाल के कारण वर्तमान बैंकिंग संकट पैदा हुआ।

इसके बाद, अमरीकी फेडरल व्यवस्था ने अमरीकी अर्थव्यवस्था में वर्तमान में देखी गई उच्च स्तर की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है। नतीजतन, बॉन्ड मूल्य में गिरावट आई और छोटे और मध्यम आकार वाले बैंक की संपत्ति बहुत कम हो गई। बैंकों के डूबने के डर से लोग बैंकों में जमा अपना धन निकालने के लिए दौड़े, अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन के आश्वासनों के बावजूद संकट बढ़ता जा रहा है और अब यह संकट तेजी से यूरोपीय बैंकों को संक्रमित कर रहा है।

समाज में, संपत्ति का सृजन मेनुफैक्चरिंग जैसे उत्पादक क्षेत्रों में पूंजी निवेश से किया जाता है, लेकिन युद्धों पर, शेयर बाजारों पर पूंजी निवेश से नहीं, जो अनुत्पादक हैं और जिनका समाज में कोई उपयोग नहीं है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

24 अगस्त 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित ईटीआईजी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में निवेश 9.2 बिलियन से बढ़कर 221.2 बिलियन डालर हो गया।

भय और जोखिम के माहौल से विमुख विदेशी निवेशक सुरक्षित जगहों की तलाश करेंगे। इसका असर प्रत्यक्ष निवेश दर पर पड़ेगा क्योंकि वे दूसरी जगह अधिक लाभ के लिए भारतीय शेयर बाजार में लगाए गए धन को निकालकर, इस धन का निवेश बड़े पश्चिमी बैंकों में करेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे देशों में जाने से हमारा रुपया और गिर जाएगा। सुरक्षित रास्तों की तलाश में अमीर लोग सोना खरीद रहे हैं। जिसके कारण भारतीय बाजार में सोने की मांग में तेजी है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के डर से हमारे निर्यात में भारी गिरावट आने की संभावना है। कोविड महामारी के दौरान निर्यात ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया है। फिर भी, अब स्थिति और बिगड़ सकती है जब हम मंदी की लंबी अवधि में प्रवेश कर रहे हैं। अमरीका में ब्याज दरों में किसी भी अतिरिक्त वृद्धि से अंततः उच्च मुद्रास्फीति होगी। और निश्चित रूप से उन देशों पर मुद्रास्फीति का असर पड़ेगा जो कि अमरीका के साथ व्यापार करते हैं। इससे हमारी वर्तमान 6.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, जो पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति के लक्ष्य से काफी अधिक है।

हमारी अर्थव्यवस्था मुश्किल से कोविड महामारी के प्रभाव से ऊभरी गई है और हमारा मध्यम अवधि का दृष्टिकोण कमजोर प्रतीत होता है। हमारा प्राइवेट (निजी) निवेश (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लगातार प्राइवेट निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन के बावजूद) कमजोर है, निर्यात में कमी, व घरेलू मांग में और गिरावट आ रही है। अमरीकी बैंकिंग संकट के झटकों से भारत सहित विकासशील देशों में वित्तीय संकट पैदा होगा।

2008 में अमरीका में सबसे बड़ी कॉर्पोरेट विफलता – लेहमन ब्रदर्स के दिवालिए से जुड़ी आर्थिक मंदी की निरन्तरता बैंकों के वर्तमान संकट का कारण है। पूंजीवादी वर्ग और इसके राज्य द्वारा एक जगह पर इस संकट से बचाव के लिए किसी पड़ाव पर उठाए गए कदमों के बावजूद ये संकट और रहस्यमय तरीके से दूसरे स्थान पर और भी अधिक हिंसक रूप से फिर से उठेंगे। यह स्पष्ट रूप से अनुत्पादक वित्त पूंजी के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। नाटो देशों और अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा जनगण पर व्यय के लिए सार्वजनिक बजट को यूक्रेन युद्ध में झोंकने से आम जनता की स्थिति दयनीय हो रही है। फ्रांस और इंग्लैंड (रेल और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल) में वर्कर्स की विशाल हड़तालें मजदूर वर्ग के कल्याणकारी उपायों पर हमलों का प्रतिरोध हैं। आम लोगों और श्रमिकों को आज पूंजीवाद के अस्तित्व को संकट से बचाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

वर्तमान बैंकिंग संकट से उभरने के लिए साम्राज्यवाद को दुनिया भर में लाखों लोगों की अमन के लिए गूँजती आवाजों पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल रूस–यूक्रेन और ताइवान तट पर छिड़ी जंगी होड़ को बंद करना चाहिए।

भाकपा ने की दवा की कीमतों में बढ़ोतरी की भर्त्सना

पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल ने एक अप्रैल से जरूरी दवाओं की कीमत में की जा रही 10 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी की भर्त्सना की है और केंद्र सरकार से बढ़ती कीमत पर रोक लगाने की मांग की है।

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बयान जारी कर कहा कि एक अप्रैल 2023 से 384 प्रकार की दवाएँ महंगी हो जायेगी। जिसमें दर्द निवारक, संक्रमण रोधी दवाएं, हृदय संबंधी दवाएं, कैंसर, एंटीबायोटिक्स आदि जीवनोपयोगी दवाएं शामिल हैं। एक अप्रैल से उपभोक्ताओं को नियमित और आवश्यक दवाओं के लिए अधिक कमत भुगतान करना होगा। भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार ने दवा की कीमत में बढ़ोतरी कर निजी दवा कंपनियों को लूटने का मौका दे रही हैं। मोदी सरकार में प्रत्येक साल दवा की कीमत में बढ़ोतरी की जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। देश में आवश्यक दवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी दवा कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक साल मोटी रकम चंदा के रूप में देती है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा हर साल आवश्यक दवाओं की कीमत में बढ़ोतरी की स्वीकृति दे दी जाती है। आवश्यक दवाओं की कीमत में बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा। कोई ऐसा परिवार नहीं है, जिनके घरों में प्रत्येक महीने हजारों रुपये की दवा नहीं खरीदी जाती हो। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें की जाए तो 2005 से लगातार कुछ अंतराल को छोड़कर राज्य का स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास रहा है। भाजपा ने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस तरह चौपट कर दिया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा नेताओं के कई निजी मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आजादी के 75 वर्ष बाद भी राज्य की अधिकांश आबादी, खासकर ग्रामीण आबादी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के इंतजार में ही है। आज भी राज्य के लाखों लोग इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने को विवश हैं। अधिकांश ग्रामीण आबादी आज की तारीख में भी स्थानीय हकीम पर इलाज के लिए निर्भर हैं। ऐसा हो भी क्यों न क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार प्रति एक हजार की आबादी पर एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ ग्यारह हजार की आबादी पर एक डॉक्टर है जबकि बिहार में उनतीस हजार की आबादी पर एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर है। यह आंकड़ा भी स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। यही वजह है कि कोरोना काल में देश के कई राज्यों की भांति बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल गई थी। भाकपा राज्य सचिव ने केंद्र सरकार से दवा की बढ़ी हुई कीमत पर रोक लगाने की मांग की है।

मंहगाई, बेरोजगारी के खिलाफ भाकपा का प्रदर्शन

जौनपुर: पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सिंहभूम जिला परिषद द्वारा आम जनता को प्रभावित करने वाले ज्वलंत मुद्दों को लेकर ''आक्रोश रैली'' निकाली गई, जो आम बागान मैदान से चलकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची। यह जुलूस देश में बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी एवं सरकारी प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में सौंपने और औने पौने दामों में बेचने के खिलाफ आम जनता के आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया था। इस जुलूस में पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्र–चाकुलिया, घाटशिला, बहरागोड़ा, पटमदा, पोटका से भारी संख्या में किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान एवं महिलाएं केंद्र सरकार के आम जन विरोधी नीतियों, जनता को त्रस्त कर रही मंहगाई, पिछले 45 वर्ष से सबसे अधिक बेरोजगारी एवं देश की राष्ट्रीय संपतियों को निजी हाथों में सौंपने एवं बेचने के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करने शामिल हुए और जुलूस के शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। जुलूस में शामिल लोग महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगार को रोजगार दो, राष्ट्रीय संपत्ति देश की, इसे बेचना बंद करो जैसे नारे लगाकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे थे। इस जुलूस का नेतृत्व जिला सचिव अंबुज कुमार ठाकुर, सचिवमंडल के सदस्य शशि कुमार, रमेश मुखी, भुनेश्वर तिवारी, ओम प्रकाश सिंह ने किया।कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अंबुज ठाकुर के नेतृत्व में पांच सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आम जनता के मुद्दों को लेकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम का ज्ञापन पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त महोदया श्रीमती विजया जाधव को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपायुक्त महोदया को बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की बिक्री एवं निजी हांथों में सौंपने के विरुद्ध पार्टी के विचार से अवगत कराया और ज्ञापन महामहिम को भेजने का आग्रह किया। इस जुलूस में सत्येंद्र सिंह, जय शंकर प्रसाद, सपन घोषाल, सवालाल महाकुड, मनसा राम महतो, मिथलेश सिंह, सूरजनाथ, जफर खान, एन एस पाल, सरकार किसकी, एआईएसएफ के लीडर विक्रम कुमार और बैंक कर्मचारी यूनियन के लीडर हीरा अरकने ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वित्तीय संकट और इसके प्रभाव

श्रीनिवास खंडेवाले

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संचालन में बैंक और वित्त की अहम भूमिका है। लोग (जमाकर्ता) अपना धन बैंकों में डालते हैं और बैंक उस धन का इस्तेमाल कंपनियों और जनता के लिए ;ण उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। इसलिए बैंक व्यवस्था, शेयर बाजार और अन्य संस्थानों का प्रबंधन किया जाना चाहिए और बैंक व्यवस्था पर पूरी निष्ठा और नैतिकता के साथ निगरानी रखी जानी चाहिए। अमरीका और यूरोप के कुछ बैंक हाल ही में ढह गए हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्याधिकारियों से कहा कि वे विदेश में ब्याज दर पर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक वित्तीय झटकों से बैंकों की सुरक्षा के की प्रति सतर्क रहें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्याधिकारियों ने मंत्री और राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि वे सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट शासन–विधि का, नियामक मानदंडों का पालन करते हैं, विवेकपूर्ण नगदी प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ–साथ मजबूत परिसंपत्ति–उत्तरदायित्व और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या लोग बैंकों के मुख्याधिकारियों के इन बयानों पर विश्वास कर सकते हैं और आश्वस्त रह सकते हैं! यदि ऐसा है तो फिर बैंकों को क्यों खतरे में घोषित किया जा रहा है? बैंक खाताधारक लगातार चिंतित हैं कि क्या उनका धन बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सुरक्षित है। यह कैसे हो सकता है कि कुछ कर्पोरेट घराने और उनके प्रमोटर अचानक सुपर रिच बन गए?

अमरीका में कॉर्पोरेट वित्तीय क्षेत्र में जो प्रमुख आर्थिक परिवर्तन सामने आए हैं, वे हैं (1) विभिन्न बैंक और वित्तीय प्रतियोगियों के बीच ब्याज दर को लेकर द्वन्द्व, जिससे अत्यधिक नगदी का प्रवाह होता है, और परिणामस्वरूप बैंक डूबते हैं, और (2) बैंक ऋण के अनुचित हिस्से को किनारे करने के लिए शेयरों और परिसंपत्तियों को अति–मूल्यांकित करने का काम। चूंकि ये बदलाव अमरीका में हुए हैं और इन बदलावों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था में फैल रहा है, इसलिए उन्हें समझना और भारत के दृष्टिकोण से उनकी गंभीरता से समीक्षा करना आवश्यक है। माइकल हडसन, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने इस घटना का वास्तविक और स्पष्ट तरीके से विश्लेषण किया है (देखें 12 मार्च 2023 को काउन्टर पंच डॉट ओआर जी में उनका लेख, ह्वाइ द बैंक क्राइसिस इज नॉट येट ओवर)।

माइकल हडसन बताते हैं कि अमरीका की 2008–09 की वित्तीय डूब का कारण आवासीय संपत्तियों के मूल्यांकन साथ–साथ उधारकर्ताओं के मूल्यांकन में की गई धोखाधड़ी के कारण हुआ था। बैंकों ने उस समय धोखेबाजी की थी। इस बार, 2023 में, ब्याज दरों में लगातार वृद्धि हुई है। लगभग 14 सालों से बैंक कर्ज पर, रेहन (मोर्टगेज) पर, बांड आदि पर ब्याज दर कम थी। इसकी तुलना में, उच्च ब्याज दरों ने आज की परिसंपत्तियों की कीमतों को बढ़ाया है। आज भी पहले उन कम ब्याज दरों पर खरीदी गई दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का और कीमतों पर हिसाब लगाया जाना है, जो वर्तमान कीमतों और ब्याज दरों पर नुकसान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लगभग 14 सालों से बैंक स्वार्थीपूर्ण ढंग से कर्ज पर, रेहन (मोर्टगेज) पर, बांड आदि पर ब्याज दर कम थी। इन परिसंपत्तियों से ब्याज कमाया गया और इसलिए उनकी कीमतें कम थीं।

वास्तव में, 2022 में आसान से मिलने वाला धन और कम ब्याज दरों का 14 साल का युग खत्म हो गया था। इस अवधि के दौरान, बैंकों ने जमाकर्ताओं की जमा राशि पर मुश्किल से 0.1 या 0.2 प्रतिशत ब्याज दिया। लेकिन बैंक स्वार्थीपूर्ण ढंग से ऋण, गिरवी, क्रेडिट कार्ड आदि पर अधिक शुल्क लगा रहे थे। जब कोरोना बाद के समय में अर्थव्ययवस्था के उभरने के कारण कारण ब्याज दरों में वृद्धि शुरू हुई, तो जमाकर्ताओं और धन गिरवी रखने वालों ने कम ब्याज वाली परिसंपत्तियों से पैसा निकालना शुरू कर दिया, ताकि निकाले गए धन को उच्च ब्याज देने वाले अल्प अवधि के बन्ड में निवेश किया जा सके। इससे जमाकर्ताओं को भुगतान किए जाने वाले नगदी कोष की कमी हो गई। इस तरह मार्च 2023 में एक ही नहीं बल्कि तीन बैंक ढह गए।

क्या भारत में ब्याज दरों में निरंतर वृद्धि के कारण इतने बड़े पैमाने पर धन के निवेश में बदलाव हो सकता है? हडसन ने लिखा कि अमरीका के लिए यह वास्तविक वित्तीय संकट है, यह बैंक व्यवस्था से परे है। यहां तक कि ब्याज दर वृद्धि का उद्देश्य मजदूरी के दाम को कम रखना है।

जब संकट आता है, हम एक नियामक ढूंढना शुरू कर देते हैं। हडसन के एक बहुत ही दुखद लेकिन वैचारिक रूप से यथार्थवादी टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि नियामकों का 'सुरंगी दृष्टिकोण' है। सिलिकॉन वैली बैंक के संदर्भ में हडसन ने पूछा कि फेडरल रिजर्व के परीक्षक कहां थे। उन्होंने आगे कहा कि (प्र. 3) "नियमों से खेलने वाले भ्रष्टाचार ने इस तरह के सुरंगी ष्टिकोण रेगुलेटर्स और परीक्षक का चयन करने में बड़ी भूमिका निभाई है.. . वे सुरंगी दृष्टिकोण रेगुलेटर्स और परीक्षक हमारी वित्तीय व्यवस्था में किसी संरचनात्मक खामी को नकारने के लिए चुने गए थे। नियामक 'सच्चे विश्वासी' हैं कि वित्तीय बाजार 'ऑटोमेटिक स्टैबलाइजर्स' और 'आम समझ' से अपने आप में सुधार करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अति–मूल्यांकन

भारत में, हालांकि हमारा जोर उत्पादन और व्यापार में शोषण के बारे में लगातार घूमता रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमरीका और यूरोप इस नाच में आगे बढ़ गए हैं हैं और वित्तीय बाजारों में शामिल लोगों का शोषण करने में कुशल हो रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं का काम लोगों की गाढ़े पसीने की कमाई को बैंकों, बीमा कंपनियों, बांडों, शेयर बाजार, पेंशन फंडों आदि पर लगाना है। वे संबंधित वित्तीय कागजात एक दूसरे को और जनता

शेष पेज 15 पर...

केवल मिट्टी और पत्थर से नहीं बनता देश

'धीरेंदु मजूमदार की माँ' नाटक का मंचन

सी. आदिकेशवन

डालटनगंज, 16 मार्च 2023: 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन की पूर्व संध्या पर को इंदौर इप्टा की नाट्यमंडली ने ललितांबिका अंतराजनम की मलयालम में लिखी कहानी धीरेंदु मजूमदार की माँ का हिन्दी में मंचन किया। 70 मिनट चले नाटक ने दर्शकों को इस हद तक अभिभूत किया कि नाटक के दौरान हाल में चुप्पी छाई रही और कई दर्शकों की आँखें गीली हो गई।

नाटक की शुरुआत में, जया मेहता और विनीत तिवारी ने कहा कि आजादी के 75 वें साल में, आजादी के आंदोलन और इसके सेनानियों को याद रखने की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान समस्याओं के स्रोत को समझा जा सके। नाटक की प्रस्तुति में मुख्य कहानी के साथ–साथ कई संबंधित दृश्य एक अलग स्क्रीन पर चलते हैं। विनीत तिवारी मूल कहानी से इतर घटनाओं को बयां करते हुए सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं।

पूर्वी–पाकिस्तान की जनता के 1971 के दौरान अपने स्वतंत्र देश, बांग्लादेश, के संग्राम की पृष्ठभूमि में ललितांबिका अंतराजनम की मलयालम में लिखी कहानी का हिन्दी अनुवाद विनीत तिवारी ने किया है। मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं किसी भाषा, प्रांत, धर्म की सीमाओं से बंधी नहीं हैं। औपनिवेशिक गुलामी से आजादी के लिए लोगों के संघर्ष के परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ। इस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग ब्रिटिश शासन के अंत के लिए लड़े थे न कि देश के विभाजन के लिए। लेकिन ऐसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को देश के विभाजन का खामियाजा भुगतना पड़ा जो विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। धीरेंदु मजूमदार की मां, शांति मजूमदार उनमें से एक थीं। एक ऐसी माँ जिसने अपने नौ बच्चों में से चार को ब्रितानी सरकार के खिलाफ लड़ाई में और दूसरे चार बच्चों को पाकिस्तान की तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई में कुर्बान कर दिया था।

पूर्वी बंगाल में 90 साल पहले जन्मी शांति मजूमदार जो 9 साल की उम्र में शादी के बाद राजा साहेब की हवेली में दाखिल हुई। उन्होंने अपने समय के सामाजिक मानदंडों को निभाते हुए कभी अपने पति राय बहादुर के सामने अपनी आवाज नहीं उठाई। औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ लड़ाई में एक ओर उनका अपने विद्रोही बेटों की मदद करना और दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान पति राय बहादुर के प्रति कर्तव्य पालन इन दोनों स्थितियों के बीच झूलती शांति की कहानी एक नया मोड़ लेती है जब वह पदमा नदी के तट पर क्रांति नायक सूर्य सेन से मिलती है, जो कि एक योगिनी के भेष में खुद उनके अपने घर के पूजा के मंदिर के बगल वाले कमरे में भूमिगत रहते हैं। नाटक के ये अंश बखूबी चित्तगाँव विद्रोह, चित्तगाँव विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सूर्य सेन के साथ–साथ तारकेश्वर, गणेश घोष, सावित्री और कल्पना दत्त का परिचय कराते हैं, दूसरे शब्दों में आजादी की लड़ाई की कम सुनी कहानी को बताते हैं।

यहाँ शांति मजूमदार, जो अन्तःपुर (घर के अंदरूनी भाग) में रहती हैं, वे बंग माता के रूप में उस समय एक नया जन्म लेती हैं जब उनके बेटे ने उनसे शपथ ली कि वह उनकी शहादत पर रोएंगी नहीं। बेटे को दिए गए वचन को निभाते हुए शांति मजूमदार बेटे की मौत पर तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाती हैं। इस करुणामयी दृश्य ने लेखक समेत अन्य दर्शकों की आंखे नम कर दी थी।

यहां से, शांति मजूमदार स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। आजादी के लिए लंबे, निरंतर और अथक संघर्षों के बावजूद जब आजादी की पूर्व संध्या पर धर्म और समुदाय के नाम पर सांप्रदायिक दंगा नोआखाली में छिड़ जाता है तो शांति मजूमदार इस सांप्रदायिक हिंसा की आग बुझाने के प्रयास में महात्मा गांधी के साथ नोआखाली में सांप्रदायिक–सद्भाव के लिए काम करती है।

पश्चिम पाकिस्तान के विरूद्ध मुक्ति संघर्ष के दौरान, मुक्ति वाहिनी के सैनिक शांति मजूमदार को भारत ले आते हैं। उन्हें अपनी मातृभूमि, भारत में शरणार्थी कह कर संबोधित किया जाता है तो सवाल उठता है कि क्या शांति मजूमदार भारत के आजादी की लड़ाई की एक सिपाही है? क्या वह शरणार्थी है? क्या वह आदिवासी है? या वह विदेशी है? मूल कहानी के साथ–साथ अपने ही देश में विस्थापित होते आदिवासियों की दास्तान, विभाजन से पहले से देश के किसी हिस्से में बसे मुसलमानों की व्यथाएं, महाराष्ट्र में प्रांतीयता के आधार पर अपने ही देश में गैर बनाए गए उत्तर भारत के लोगों की आपबीती, अवैध नागरिकता के सवाल का सांप्रदायिक राजनीतिकरण करते हुए नागरिकता ससोंधन कानून के नाम पर पूर्वी सीमावर्ती इलाके में बांग्लादेश विभाजन के बाद बसाए गए लोगों में से मुसलमानों को घुसपैठिया बनाने की राजनीति के लघु दृश्य भी चलते हैं जो की नाटक को समसामयिक बनाते हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय पहचान को धर्म विशेष की पहचान से जोड़ने के प्रयासों से उपजे एक नए संकट को बयान करते हैं।

वरिष्ठ अभिनेत्री फ्लोरा बोस ने कहानी की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ दर्शकों से हिंदुस्तान की आजादी के लिए कई नामहीन, रूपहीन लोगों की कुर्बानी के बरक्स हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार की अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति वैमनस्यता बढ़ाने वाली साम्प्रदायिक विचारधारा और साम्प्रदायिकता को आंदोलित करने वाली राजनीति पर एक बार फिर से

शेष पेज 14 पर...

बीकेएमयू का 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन दो नवम्बर से पटना में

पटना में विशाल रैली से शुरू होगा महाधिवेशन

किरणेश कुमार

उमगांवः बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का 15वां बिहार राज्य सम्मेलन पंचरत्न शहीद कामरेड योगेन्द्र, कामरेड जयशंकर, कामरेड रामऔतार, कामरेड रामललित एवं बौकू नगर और कामरेड शहीद संतु महतो सभागार, उमगाँव मधुबनी में 20 से 22 मार्च 2023 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में भारतीय खेत मजदूर यूनियन (बीकेएमयू) का 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन दो से पांच नबम्बर तक पटना में आयोजित करने का फैसला लिया गया। इस मौके पर दो नवबंर को पटना में विशाल रैली निकाली जाएगी। जिसमें पांच लाख से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। सम्मेलन की शुरुआत शहीद नगर उमगावं में संगठन के राज्य अध्यक्ष पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय के द्वारा झंडोतोलन के साथ हुई। इस मौके जनसेवा दल के साथियों ने झंडे की सलामी दी है और प्रतिनिधि साथियों ने शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की। झंडोतोलन के बाद एक आकर्षक रैली सम्मेलन स्थल से लेकर शहीद स्मारक तक निकली। 20 मार्च 1990 को शहीद पांच साथियों की याद में बनाई गए शहीद स्मारक पर नेतृत्वकारी साथियों और प्रतिनिधि साथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। रामचंद्र पासवान के नेतृत्व में इप्टा के साथियों ने जनवादी गीतों के माध्यम से रैली में आये साथियों में जोश ला दिया। बारिश के बावजूद रैली में आये साथी भींगते हुए आमसभा में अपने नेताओं के भाषण सुनते रहे। महती सभा की शुरुआत सीपीआई के राज्य सचिव, यूनियन के राज्य अध्यक्ष व पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय की अध्यक्षता में हुई।

आम सभा को सम्बोधित करते हुए भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासचिव गुलजार सिंह गोरिया ने कहा देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। देश की सत्ता पर तानाशाह सरकार काबिज है। हक की बात बोलने वाले, आम जनता के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सांस्कृतिक, साहित्यिक लोगों को जेल के अंदर बंद किया जाता है। महगांई, बेरोजगारी एवं द्वेष घृणा के माहौल से आम लोग परेशान है। किसानों एवं मजदूरों के तमाम अधिकार का हनन किया जा रहा है। देश में मजदूरों को संगठित होकर जनसमस्याओं के लिए आंदोलन तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बिहार खासकर मधुबनी की धरती संघर्ष आंदोलन एवं कुर्बानियों की धरती है। पूर्व सांसद, पूर्व महासचिव नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा मजदूरों के मुंह का निवाला पूजीपतियों की संपत्ति बन रहा है। देश की संपत्ति को बेचकर कुछ चुनिंदें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज देश में 73 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के बुनियादी सवालों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करना पडेगा। खेत मजदूर यूनियन का यह सम्मेलन संगठन को मजबूत करते हुए आंदोलन तेज करने की योजना बनाएगी। आम सभा को बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का महासचिव जानकी पासवान, कार्यकारी अध्यक्ष विधायक सूर्यकांत पासवान, सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम प्रकाश नारायण, राजश्री किरण, पूर्व सांसद तेजनारायण सिंह यादव, सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मिथिलेश झा, किसान नेता कृपानंद आजाद, मनोज मिश्र, लक्ष्मण चौधरी, राजेश कुमार पांडेय, हरलाखी प्रखंड के पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडेय बाला जी, सूर्यनारायण महतो, खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष रामनारायण यादव, जिला सचिव रामचंद्र पासवान, सम्मेलन के स्वगताध्यक्ष बलराम यादव, आनंद कुमार झा, महेश यादव, खेत मजदूर यूनियन के राज्य परिषद सदस्य जामुन पासवान, बालकृष्ण मंडल, उपेंद्र सिंह, अजय कुमार वर्मा, राज्य परिषद सदस्य किरणेश कुमार, अशेश्वर यादव, गिरिंद्र राय, जामुन शुक्ला, बैद्यनाथ ठाकुर, सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सदस्य विजेंद्र केशरी, जितेंद्र कुमार सहित कई स्थानीय साथी भाग लिए।

अध्यक्षीय संबोधन में रामनरेश पांडेय ने कहा बिहार में खेत मजदूरों एवं किसानों के सवालों पर, मध्यमवर्गीय परिवारों के मुद्दों को लेकर 8 एवं 9 जून 2023 को राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अंबेडकर जयंती 15 अप्रैल से 14 मई तक राष्ट्रीय पदयात्रा कार्यक्रम गांव गांव किया जायेगा। केंद्र सरकार के गरीब विरोधी सवालों के खिलाफ मधुबनी की धरती के पुराने शहादत को याद करते हुए सम्पूर्ण बिहार ने आंदोलन के तेज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पेंशन, आवास, न्यूनतम मजदूरी की राशि एवं रोजगार दिवस आदि सभी में वृद्धि के मुद्दों को लागू करवाने का संघर्ष तेज होगा। बिहार के बुनियादी समस्या बाढ़ सुखाड़ बिजली संकट के निदान के लिए बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण के मांग को लेकर 03 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार के समक्ष दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

तीन दिवसीय सम्मेलन में आम सभा के बाद संध्या 7 बजे से सम्मेलन का सत्र प्रारंभ होगा जो प्रति दिन दो सत्रों में संचालित होते हुए 22 मार्च तक चलेगा। सम्मेलन में विगत वर्षो के संगठन के कार्यो, आंदोलनों का मूल्यांकन एवं आगामी वर्षो के लिए ने नेतृत्व का गठन एवं आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। सम्मेलन एवं आमसभा की सफलता में हरलाखी एवं मधवापुर के संगठन एवं आम लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। केंद्र की मोदी सरकार मजदूर विरोधी बाढ़, सुखाड़ के स्थाई निदान और हाई डैम निर्माण के लिए तीन अप्रैल को दिल्ली में धरना दिया जायेगा।

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के 15वें बिहार राज्य सम्मेलन का प्रतिनिधि सत्र राज्य अध्यक्ष व सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय, सूर्यकांत पासवान, ओमप्रकाश नारायण, बालकृष्ण मंडल और लालती देवी की अध्यक्षमंडली में शुरू हुई। दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन का उदघाटन करते हुए भारतीय खेत मजदूर यूनियन के पूर्व महासचिव, पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा देश में बेशुमार बेरोजगारी से आम लोग परेशान हो चुके है। केंद्र सरकार द्वारा नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने के वाबजूद अपने मजदूर विरोधी एवं पूंजीपति पक्षी नीतियों को लागू करने में व्यस्त है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय कानून का दर्जा संगठन के लगातार संघर्ष एवं आंदोलन के बदौलत मिला। केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करने की साजिश कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के पेश किए आम बजट में मनरेगा में भारी कटौती की गई है। महंगाई के कारण मजदूरों एवं किसानों का मनोबल नीचा हुआ है परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर–किसान आत्महत्या कर रहे है।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि केंद्र देश के तमाम संस्थाओं को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। खेत मजदूर यूनियन का संगठन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मजदूरों को संगठित कर धारदार आंदोलन करेगी। घृणा पैदा कर देश और राज्य नही चलाया जा सकता। उन्होंने कहा बिहार के मध्यमवर्गीय जनता की आवाज बनकर, मेहनतकश किसान मजदूर के सवालों पर केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। बिहार के बंद उद्योग को चालू करना, सभी बेघरों को घरों की व्यवस्था करना, बासविहीन भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने, 600 रू. न्यूनतम मजदूरी एवं साल में 200 दिन रोजगार देने की गारंटी करने के सवाल पर मजबूत संघर्ष करने की आवश्यकता है। राजनीतिक और सांगठनिक रिपोर्ट संगठन के प्रदेश महासचिव जानकी पासवान ने पेश किया। भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव गुलजार सिंह गोरिया ने कहा कि केंद्र में सत्ता में बैठी मोदी सरकार मजदूर विरोधी है। मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। मनरेगा की राशि में की गई कटौती के खिलाफ 30 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा।

सम्मेलन का अभिनन्दन सीपीआई के जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, महिला नेत्री राजश्री किरण, सीपीआई राज्य परिषद सदस्य राकेश कुमार पांडेय, पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडेय आदि ने किया। बहस में तीन दर्जन से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर भूमि सुधार के लिए गठित डी. बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करने और सभी भूमिहीनों को पांच पांच डिसिमिल वास की भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही नल जल योजना के नाम पर तालाब के भिंडा पर पर गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई।

सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर बाढ़, सुखा एवं बिजली का स्थाई निदान के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर तीन अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि बिहार में बाढ़ और सूखा सबसे बड़ी त्रासदी है। एक ही साथ बिहार के कई जिलों में बाद रहती है तो कई जिलों में सुखा से आम लोग परेशान रहते हैं। इसके स्थायी निदान के लिए कोशी नदी के उदगम स्थल बराह, कमला नदी के उदगम स्थल शीशापानी तथा बागमती नदी के उदगम स्थल नूनथर में बहुउद्देश्यीय डैम बनाने का मुद्दा सर्वप्रथम संसद में कामरेड भोगेन्द्र झा ने प्रभावकारी ढंग से उठाये थे। इस पर भारत और नेपाल सरकार की सहमति के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई, जिसकी कई बैठक भी हुई। कुछ काम भी शुरू किया गया। फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्तमान समय में कोशी, कमला, बागमती एवं गंडक नदियों के पानी से उत्तर बिहार के जिले के लोग बाढ़ त्रासदी झेलते हैं। वहीं दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले सूखे की चपेट में रहता है। दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वह सोन नदी से जलाशय योजना, घोषणाओं एवं शिलान्यासों तक ही सिमट कर रहा गया है। गंडक योजना आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। जिस कारण इस क्षेत्र के लोग वर्षा पर निर्भर है। गेरुआ नदी में बालू के खान के चलते जलस्तर नीचे चला गया फलतः सिंचाई बाधित है। बांका जिले के लक्ष्मीपुर डैम, ओढनी डैम तथा बिलासी डैम का भी खास्ताहाल है। इस परिस्थिति में बिहार में बाढ़ और सुखा का स्थायी निदान आवश्यक है। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का यह सम्मेलन मांग करता है कि कोशी, कमला, बागमती, सोन सहित उत्तर बिहार मध्य बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों पर डैम तथा चेक डैम का निर्माण किया जाए। बिहार के नदियों से सिल्ट और गाद को हटाने की कार्य योजना बनायी जाये। कटाव से विस्थापित परिवार को पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। बिहार में बाढ़ तथा सुखा के स्थायी समाधान हेतु केन्द्र सरकार शीघ्र नेपाल सरकार से बात कर विस्तृत कार्य योजना बनाये और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें। उक्त मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर तीन अप्रैल को धरना दिया जाएगा। धरना का बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन समर्थन करता है और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करता है। किसानों को कम से कम 8 घंटा मुफ्त सिचाई के लिए बिजली दें। नवादा, शेखपुरा, नालान्दा, जुर्मुई जिला में पटवन के लिए अपर सकरी जलाश्य का निर्माण किया जाये। कोसी नदी के पश्चिमी भाग पर समस्तीपुर से खगडिया जिला डुमरी तक तटबंध का निर्माण कराया जाए, बागमती के दोनों किनारे बांध का निर्माण किया जाये। डोरडा तिलैया सिंचाई परियोजना को पूर्ण कर जल्द से जल्द से चालू किया जाये। इन तमाम योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बिहार सरकार पहल करे। केन्द्र सरकार इसे संकट का स्थायी निदान करे। पूरा कर बिहार में बाढ़ सुखाड़ एवं बिजली का स्थाई निदान किया जाए। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए। रिपोर्ट यूनियन के महासचिव जानकी पासवान ने पेश किया। जिस पर तीन दर्जन से अधिक साथियों ने बहस में भाग लिया।

सम्मेलन के अंतिम दिन 22 मार्च को नई राज्य परिषद का चुनाव किया गया। राज्य परिषद की पहली बैठक में पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से सूर्यकांत पासवान अध्यक्ष, जानकी पासवान महासचिव, ओमप्रकाश नारायण कार्यकारी अध्यक्ष, पुनित मुखिया उप महासचिव, रामनरेश पांडेय, सुधीर कुमार, लालती देवी व अनिल प्रसाद उपाध्यक्ष चुने गए जबकि रमाकांत अकेला, अर्जुन राम, प्रमोद शर्मा, राजेन्द्र सहनी व किरणेश कुमार राज्य सचिव चुने गए। वहीं सत्येंद्र कुमार कोषाध्यक्ष और रामपुकार मुखिया कार्यालय सचिव चुने गए। सम्मेलन का समापन इंटरनेशनल गान के साथ हुआ। तीन मई को होने वाली राज्य परिषद की बैठक में तीन मई को स्वागत समिति गठित की जाएगी। सम्मेलन में आगामी लक्ष्य का भी निर्धारण किया गया। पूरे राज्य 14 अप्रैल को डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आठ और नौ जून को जिला मुख्यालय पर आयोजित सत्याग्रह में अधिक से अधिक खेत मजदूरों की भागीदारी होगी। खेत मजदूरों के सवालों को लेकर जन आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया।

संदर्भ: हिन्डनबर्ग रिपोर्ट

अडानी के कारनामों पर जेपीसी जांच से क्यों घबराती है मोदी सरकार?

आर.एस. यादव

24 जनवरी 2023 को हिन्डनबर्ग रिपोर्ट सामने आयी जिसमें भारत के सबसे बड़े कारपोरेट घराने–अडानी कारपोरेट घराने पर आरोप लगाया गया है कि धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर उसने अपने शेयरों के मूल्य बढ़ाये और उससे लाखों–करोड़ रुपये बनाए; उसने टैक्स हेवन देशों में फर्जी कंपनियां बनाकर उनके जरिये लाखों–करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है, आदि।

रिपोर्ट में उन फर्जी कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिसमें सभी को स्वयं गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी या अडानी के करीबी लोग चलाते हैं। ये फर्जी कंपनियां क्या कारोबार करती हैं, इसका कोई अता–पता नहीं; निशान तक नहीं। पर इन फर्जी कंपनियों का अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों और उसकी प्राइवेट कंपनियों के साथ लाखों–करोड़ों रुपयों का लेन–देन होता रहा है हिन्डनबर्ग रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि इन फर्जी कंपनियों के पास ये लाखों–करोड़ रुपए कहां से आए?

हिन्डनबर्ग रिपोर्ट का इशारा है कि यह अडानी का ही पैसा है जो ओवर–इन्वॉयसिंग या अंडर इन्वॉयसिंग और धोखाधड़ी के अन्य तरीकों से कमाया गया है। हिन्डनबर्ग के अनुसार, भारत के शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी को अडानी के इस तमाम धोखाधड़ी के कारनामों की जानकारी है और वह अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। हिन्डनबर्ग रिपोर्ट ने इसी तरह के अनेकानेक आरोप लगाए हैं।

यह आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला तो किसी व्यापक जांच से ही संभव है। सरकार का यह कहना काफी नहीं कि सेबी जांच कर रहा है क्योंकि सेबी पर तो आरोप ही है कि इस धोखाधड़ी में सेबी भी शामिल है। ऐसे में सेबी द्वारा जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता।

यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में बहस किए जाने और मामले की तह में जाने के लिए एक संसदीय समिति द्वारा जांच किए जाने की मांग की। परंतु सरकार इस मामले में न किसी बहस के लिए तैयार है और न ही संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने के बारे में।

हिन्डनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद

विपक्ष ने जब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सूरत में कई वर्ष पुराने एक भाषण के संबंध में भाजपा के एक नेता द्वारा दायर मुकदमा तुरत–फुरत शुरू कर दिया गया और राहुल गांधी को दो साल की सजा हासिल कर ली गई। मामले की टाइमिंग और टोन से न्यायपालिका की साख भी सवालों के घेरे में आ गई है। जिस तरह फैसले के तुरंत बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म किया गया और उन्हें आवंटित मकान को खाली करने का आदेश दिया गया, वह सब हिन्डनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अडानी परिवार के साथ सरकार की गैर–वाजिब नजदीकी और अडानी परिवार को फायदे पहुंचाने के सरकार के विभिन्न कदमों के रोशनी में आ जाने के कारण मोदी सरकार की हो रही किरकिरी से ध्यान बांटने की कोशिश तो है ही, विपक्ष को डराने–धमकाने, विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश भी है।

विपक्ष संसद में लगातार और दृढ़ता के साथ मांग कर रहा है कि जेपीसी से जांच कराई जाए। मोदी सरकार का रवैया है, संसद चले या न चले, किसी भी सूरत में इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए नहीं भेजा जाएगा। सरकार संसद को चलने नहीं दे रही। लोकसभा और राज्य सभा जैसे ही शुरू होती है विपक्ष द्वारा जेपीसी द्वारा जांच की मांग की जाती है। खिसियाई सरकार को कोई जवाब नहीं सूझ रहा; भाजपा के लोग विपक्ष के, खासतौर पर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं और दोनों सदनों की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। विपक्ष बार–बार संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है। एक दिन तो विपक्ष ने संसद की पहली मंजिल पर जाकर भी प्रदर्शन किया जो एक विरल घटना थी।

हिन्डनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद प्रतिदिन यही सिलसिला जारी है।

मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति का गठन किया है। पर उसकी जांच के विषय में हिन्डनबर्ग रिपोर्ट में अडानी कारपोरेट घराने द्वारा धोखाधड़ी और घोटालों की जांच का विषय शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति को जो काम सौंपा गया है उसमें मुख्यतः यह शामिल है कि हिन्डनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। समिति गठित करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समिति का गठन ''हाल के अतीत में शेयर बाजार में जिस तरह की हलचल देखी गयी है भारतीय निवेशकों को उसमें बचाने के लिए'' और ''इस समय जो नियामक तंत्र है उसके मूल्यांकन के लिए और नियामक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सिफारिश देने के लिए'' किया गया है।

जाहिर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी द्वारा अडानी के विरूद्ध लाखों–करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप या विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री और अडानी कारपोरेट घराने के बीच संबंधों के संबंध में जांच करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अतः संसदीय समति द्वारा इस मामले में जांच के लिए विपक्ष की मांग को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति जांच कर रही है।

जरूरी नहीं कि हिन्डनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप लगाए हैं वे सही ही हों। पर इसका फैसला कैसे हो? सरकार का यह कहना काफी नहीं कि सेबी जांच कर रहा है। सेबी से जांच की क्या उम्मीद की जा सकती है जबकि हिन्डनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, अडानी के धोखाधड़ी के इस गोरखधंधे में सेबी और अन्य सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत रही है?

इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत के मीडिया का रवैया नोट करने योग्य है। ''लव जेहाद'' और ''धर्मान्तरण'' और अन्य फूटपरस्त सांप्रदायिक मुद्दों या अभिनेता सुशान्त राजपूत की आत्महत्या जैसे मामलों को हैरतअंगेज तरीके से सनसनीखेज बनाकर उछालने वाला हमारा मीडिया–अखबार और टीवी चैनल–हिन्डनबर्ग रिपोर्ट में अडानी कारपोरेट घराने के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लगभग नजरन्दाज करने की नीति पर चलता दिखायी पड़ रहा है क्योंकि प्रकारान्तर से यह आरोप सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं।

कांग्रेस ने हिन्डनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अनेक प्रश्न सरकार से किए हैं जिनमें अडानी परिवार के साथ प्रधानमंत्री की नजदीकी और अडानी घराने को नाजायज फायदा पहुंचाने के संबंध में सवाल किए गए हैं।

मीडिया ने इन प्रश्नों को लगभग ब्लैकआउट किया है। भारत का मीडिया डरा हुआ है या सरकार के दबाव में है!

इस रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद अडानी द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी और घफलों–घोटालों के सम्बंध में खोज करने के लिए अधिकांशतः हमारा मीडिया क्यों तैयार नहीं? हिन्डनबर्ग रिपोर्ट द्वारा अडानी पर लगाए गए आरोपों और अडानी–मोदी के बीच नजदीकी सम्बधों और प्रधानमंत्री द्वारा अडानी घराने को पहुंचाए गए नाजायज फायदों के विपक्ष के आरोप के सम्बंध में तथाकथित ''खोजी पत्रकारिता'' क्यों खामोश है?

कुछ सामयिक मुद्दे और घटनाक्रम

आर.एस. यादव

सरकार नपुंसक, इसलिए हो रहे नफरती भाषण

नई दिल्ली, 29 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आदेश का पालन करने का विश्वास दिलाने के बावजूद हिन्दू संगठनों द्वारा नफरत पैदा करने वाले भाषणों पर कार्रवाई न करने पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल किया–''क्या सरकार नपुंसक है? यदि वह नफरत पैदा करने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो आखिर सरकार है क्यों?'' राजनीति और धर्म को अलग–अलग रहने की जरूरत को रेखांकित करते हुए पीठ ने कहा कि ''जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, ऐसे भाषण समाप्त हो जाएंगे''।

नफरती भाषणों को ''एक दुष्चक्र'' करार देते हुए न्यायालय ने कहा कि ''तुच्छ तत्वों'' द्वारा ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं। लोगों को खुद को संयमित रखना चाहिए। हमने अपने हालिया फैसले में भी कहा है कि राजनीति को धर्म से मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

पीठ ने नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने को लेकर महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर दिन ''तुच्छ तत्व'' टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं।

सुनवाई के दौरान पीठ ने हिन्दू समाज के वकील से कहा, ''सबसे महत्वपूर्ण चीज मर्यादा है। कुछ बयान दिए जाते हैं जैसे ''पाकिस्तान चले जाओ।''.....असल में, उन्होंने ही इस देश को चुना है। वे तुम्हारे भाई–बहन हैं।'' जस्टिस जोसफ ने कहा, ''सहिष्णुता मतभेदों को स्वीकार करना है। यदि आप महाशक्ति बनना चाहते हैं तो कानून का शासन होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से नफरत पैदा करने वाले भाषणों और बयानों की तरफ ध्यान आकर्षित कराता रहा है और इस बात पर जोर देता रहा है कि सरकार ऐसे भाषणों और बयानों को देने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के बार–बार के आदेशों के बावजूद सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या इसका कारण यह नहीं है कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नफरत पैदा करने वाले भाषण करते रहते हैं, अल्पसंख्यकों के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करना उनके चुनाव अभियान का मुख्य हिस्सा रहता है और जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि आवश्यक कार्रवाई करे वह आंखें मूंदे रहता है? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के देखादेखी भाजपा और आरएसएस के लोग और भी अधिक उन्मादपूर्ण तरीके से इसी काम में जुट जाते हैं। टीवी चैनलों पर अनेक एंकर भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उत्तेजनापूर्ण और भड़काने वाली बातें कह शासक पार्टी के चहेते बनते हैं।

नफरती भाषणों के संबंध में जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं करती तो केंद्र सरकार की तरफ पेश वकील ने कहा कि ऐसे 18 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। मगर उन पर कार्रवाई क्या हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं था।

छिपी बात नहीं कि किस राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता जब भी बोलते है, नफरत की भाषा बोलते हैं, अल्पसंख्यकों के विरूद्ध जहर उगलते हैं।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसफ ने कहा, ''हम दुनिया में नम्बर एक होना चाहते हैं परंतु हमारे समाज में यहां अंदर क्या हो रहा है.....यदि बौद्धिक वंचना है तो आप इस देश को नम्बर एक पर नहीं ले जा सकते। बौद्धिक वंचना केवल तब आती है जब असहिष्णुता होती है, ज्ञान का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है।

उन्होंने सकल हिन्दू समाज के वकील से कहा, ''हम जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधान हैं। उनको लागू किया जाना चाहिए। शक्ति है.....परंतु शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में उस समुदाय विशेष के सदस्यों के साथ क्या होता है जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं? उनके पास भी संविधान के अंतर्गत वह गारंटीशुदा अधिकार हैं....जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी।.....यह देश है जिसने सांप्रदायिक विरासत के लिहाज से समूची दुनिया को रोशनी दी है। आप आज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?.....सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता केवल यह नहीं है कि आप किसी के साथ केवल रह रहे हैं बल्कि सहिष्णुता का अर्थ कि आप उन्हें साथी नागरिकों की तरह स्वीकार कर रहे हैं।''

यह स्पष्ट करते हुए कि हमारी आबादी के अधिकांश लोग सहिष्णु हैं, जस्टिस जोसफ ने कहा परंतु एक तबका है जो सहिष्णु नहीं। उन्होंने आगे कहा, ''जिस इलाके में आप रहते हैं लोग आप के बारे में अनेक बातें कहते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जो अपमानजनक हैं।.....एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसका सम्मान है। धन–दौलत या स्वास्थ्य नहीं, आपका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह के बयान–जैसे कि ''पाकिस्तान चले जाओ''– लगातार दिए जाते हैं, उनसे आपका सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाता है।..... उन्होंने इस देश को चुना है, वे उस समुदाय के लोग हैं जिन्होंने इस देश को चुना है। वे आपके भाइयों–बहनों जैसे हैं।..... हम जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि बात इस हद नहीं जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस के. एम जोसफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, '' हर तरफ के ''तुच्छ तत्व'' नफरत पैदा करने वाले भाषण कर रहे हैं, सवाल यह है कि हम जा कहां रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू और अटलबिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर–दराज से भी आते थे। .....उनके भाषणों को सुनें। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ''मध्य रात्रि में स्वतंत्रता'' भाषण सुनें। दुर्भाग्य से, जिन लोगों में कोई समझ ही नहीं है, वे ''तुच्छ तत्व'' हैं और नफरती भाषण दे रहे है। सवाल यह है कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं?

देश के बिगड़ते हालात

2 फरवरी 2023 को एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''हमने हेट स्पीच (सांप्रदायिक नफरत पैदा करने वाले भाषणों) के खिलाफ बार–बार आदेश दिए हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करता''। जस्टिस के.एम. जोसफ, अनिरुद्ध बोस और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने उस याचिका की सुनवाई करते समय यह टिप्पणी की जिसमें हिन्दू जन–आक्रेश मोर्चा द्वारा 5 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे देश में बिगड़ते हालात का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार पालन न करे, यह एक असाधारण एवं अत्यंत खतरनाक स्थिति है।

भाजपा/आरएसएस से जुड़े लोग या उनसे प्रेरित या संरक्षणप्राप्त लोग अल्पसंख्यकों के विरूद्ध जहर उगलते रहते हैं, सरकारें कुछ नहीं करती। वे ''धर्म–संसद'' के नाम पर बार–बार आयोजन करते रहते हैं जहां पर ''धर्म'' की कोई बात नहीं होती। उनमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रलाप किए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने, उन्हें नीचा दिखाने की बातें की जाती हैं, उनका आर्थिक एवं सामाजिक बहिष्कार करने के आह्वान किए जाते हैं, पर मजाल है कि इस तरह का जहर उगलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? भाजपा/आरएसएस से जुड़े लोगों के सभी गुनाह माफ हैं। उन्हें खुली छूट है, कुछ भी अंधेरगर्दी करें।

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सरकारों की भर्त्सना की है, हेट स्पीच करने वालों और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। परंतु तो भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह स्थिति देश में ''कानून का शासन'' खत्म होने की दिशा का संकेत करती है। कानून का शासन, देश का लोकतंत्र और संविधान –सभी खतरे में हैं। यह एक वास्तविक खतरा है।

कैसे–कैसे ज्ञानी लोग?

समाचारपत्र की रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू–कश्मीर के उप–राज्यपाल मनोज

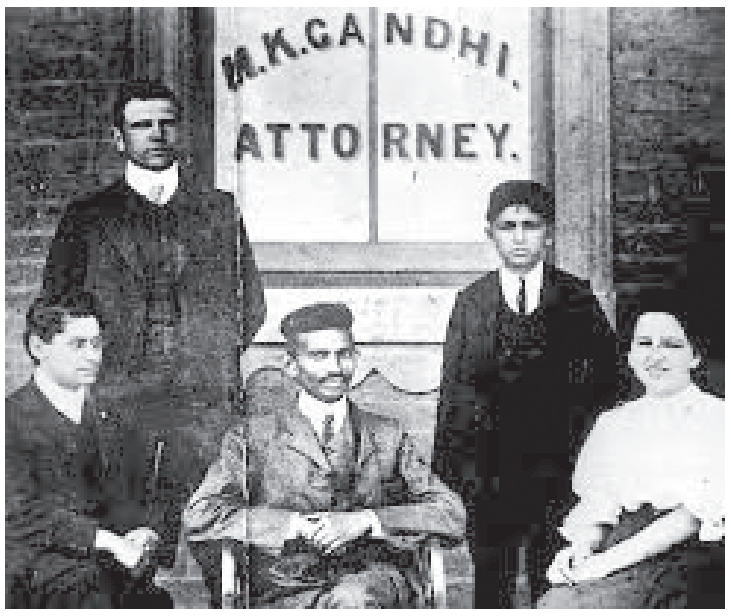

सिन्हा ने आईटीएम ग्वालियर में डॉ. राममनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान माला में भाषण करते हुए कहा कि महात्मा गांधी अशिक्षित थे; वह केवल मैट्रिक पास थे; उनके पास कोई डिग्री नहीं थी; उनके पास कानून की डिग्री नहीं थी।

अब इसका कोई क्या करे कि उन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा ''सत्य के प्रयोग'' को तो क्या, महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा।

दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे। अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए उन्हें एक भारतीय कारोबारी अब्दुल्ला सेठ अफ्रीका ले गए थे जहां उन्होंने उनके मुकदमे लड़ें। अफ्रीका में रहते ही उन्होंने सत्याग्रह के सिद्धांत को विकसित किया किया, उसको अपनाया; वहां रहने वाले भारतीयों के हितों के लिए सत्याग्रह करते हुए लड़ाई लड़ी।

महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने इंगलैंड गए थे। लंदन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ''इनर टेम्पल'' लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की डिग्री ली थी।

पर एक उप–राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं। अशिक्षित वह हैं या महात्मा गांधी?

मोदी सरकार में राज्यपाल या उपराज्यपाल या किसी भी अन्य बड़े से बड़े या संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए किसी योग्यता या शिक्षा या अनुभव की जरूरत ही क्या है? इतना ही काफी है कि वह गाय के गोबर और मूत्र के महात्मय को समझता हो, साथ ही आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हो!

दंगों में धार्मिक जुलूसों के रास्ते क्या भूमिका अदा करते है?

नागरिकों और वकीलों के एक समूह ने यह सामने लाने के लिए एक 176 पृष्ठ की रिपोर्ट प्रकाशित की है कि किस तरह धार्मिक जुलूसों के आयोजक हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर कुछ सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील रास्तों को अपने जुलूस के लिए चुनते हैं।

''सिटिजन एंड लॉयर्स इनिशिएटिव'' द्वारा तैयार इस रिपोर्ट का नाम है–''रुट्स ऑफ रैथ; वेपनाइजिंग रिलीजियस प्रोसेशन्स; कम्युनल वॉयलेन्स ड्यूरिंग रामनवमी एंड हनुमान जयन्ती (अप्रैल 2022) (कहर के रास्ते; धार्मिक जुलूसों का हथियारीकरण–रामनवमी एवं हनुमान जयन्ती के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा (2020))

इस रिपोर्ट के प्राक्कथन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रोहिन्टन एफ. नरीमन ने लिखा है:

''स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आज हमारे राष्ट्र की क्या स्थिति है?..... गोटेनबर्ग विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रसारित की है जिसका शीर्षक है ''वेरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी (वी–डेम) वार्षिक रिपोर्ट 2023''। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में लोकतंत्र के संबंध में बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि

इसमें दिए गए निष्कर्ष निकालने के लिए 60 सूचकांकों और 500 संकेतकों को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में विश्व के लोकतंत्रों को चार कैटेगरियों में बांटा गया है:

1. उदार लोकतंत्र (लिबरल डेमोक्रेसीज): जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं; कार्यपालिका के कामों पर न्यायिक एवं विधायी अंकुश होते हैं; नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है, और; कानून के सामने, कानून के शासन को समानता के साथ बनाए रखा जाता है। विश्व में 13 प्रतिशत लोकतंत्र इस किस्म के हैं।

2. निर्वाचित लोकतंत्र (इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज): जहां जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और वाक्–स्वतंत्रता होती है, पर उतनी नहीं जितनी उदार लोकतंत्र वाले देशों में होती है। विश्व में 16 प्रतिशत लोकतंत्र इस किस्म के हैं।

3. निर्वाचित तानाशाही (इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी): इस ग्रुप में बहु–पार्टी चुनाव और वाक्–स्वतंत्रता होती है, परंतु उनका स्तर वह नहीं होता कि उन्हें एक वास्तविक कार्यरत लोकतंत्र (रीयल वर्किंग डेमोक्रेसीज) माना जाए। विश्व में 44 प्रतिशत लोकतंत्र इस किस्म के हैं।

4. सीमित एवं अवरूद्ध लोकतंत्र (क्लोज्ड डेमोक्रेसीज): इसमें विश्व भर के वह तथाकथित लोकतंत्र आते हैं जहां पर बहु–पार्टी चुनाव नहीं होते और वाक्–स्वतंत्रता वास्तविक अर्थ में नहीं होती। विश्व में 28 प्रतिशत लोकतंत्र इस किस्म के हैं।

''भारत के संबंध में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1975 और 1973 के सालों, जब भारत में आपातकाल घोषित किया गया था, के सिवाय, 1972 से लेकर 2020 तक भारत निर्वाचित लोकतंत्र (इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज) की कैटेगरी में रहा। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में भारत निर्वाचित लोकतंत्र (इलेक्टोरल डेमोक्रेसी) की कैटेगरी से गिरकर तीसरी कैटेगरी यानी निर्वाचित तानाशाही (इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी) की कैटेगरी में आ गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से उस स्थिति में आ गया है जो आपातकाल के वर्षों (एमरजेंसी इयर्स) में थी। एक अन्य ग्राफ यह दिखाता है कि जहां तक लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है 2012 से 2022 के वर्षों में उसमें लगातार गिरावट आई है। इसके अलावा, एकडेमिक फ्रीडम इंडेक्स (अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक) दिखाता है कि इन वर्षों में जैसा कोई चाहे उस तरह सोचने और लिखने की स्वतंत्रता में भारी गिरावट आई है।.....

भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है: ''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अंखडता को सुनिश्चित करने वाले भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं''। इन शब्दों का कम से कम अर्थ यह है कि ब्रिटिश गुलामी के जुए, जिसमें फूट डालो और राज करो की नीति शामिल थी, को उतार फेंकने के बाद एक राष्ट्र के तौर पर भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। आगे, इसका अर्थ यह है कि सरकार को किसी धार्मिक समुदाय का पक्ष लिए बगैर एक तटस्थ तरीके से कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना होगा। इसका यह अर्थ भी है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही एक वह चीज है जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के अनुशासित एवं व्यवस्थित तरीके से बदलाव की दिशा में ले जाती है। सर्वोपरि, भाईचारे, व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की अखंडता एवं एकता को सुनिश्चित करने को भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित किया गया है।

इस संदर्भ में ये याद करना भी महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान की धारा 51ए के अंतर्गत भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह :

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करे।

(ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृ त्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

(च) हमारे मेलजोल की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।''

न्यायमूर्ति रोहिन्टन एफ. नरीमन ने ''भारत के सभी राज्यों में पुलिस बलों को ''संवदेनशील बनाने के प्राथमिक महत्व'' को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उन्हें सबसे पहले ''यह जानकारी देकर किया जा सकता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान भारतीय हैं।'' (उनके इस कथन में कटाक्ष निहित है कि पुलिस के लोग मुसलमानों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं मानो वे भारतीय नागरिक नहीं)।

रिपोर्ट बताती है कि भारत के इतिहास मे ंऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां धार्मिक जुलूसों का नतीजा सांप्रदायिक झगड़ों, दंगों, अक्षम्य हिंसा, लूटपाट, संपत्ति को नुकसान और दंगा पीड़ित क्षेत्रों में निर्दोष निवासियों की त्रासदीपूर्ण मौतों के तौर पर निकला। यदि दंगों के लिए किसी एक बड़े कारक को खोजा जाए तो धार्मिक जुलूस ऐसे कारक रहे हैं जो दंगों के कारण बने। स्वतंत्रता के बाद भारत में देश के अनेक स्थानों पर, विभिन्न राजनीतिक सरकारों के अंतर्गत जो दंगे हुए हैं, उनमें बड़ी मात्रा में दंगे धार्मिक जुलूसों का आयोजन करने वालों द्वारा जानबूझ कर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रास्तों से जुलूस निकालने के कारण हुए।

इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक दंगों के अंकुरण एवं पनपने और फैलाव का एक–एक कर विश्लेषण; कुछ खास मामलों में अधिकारियों एवं पुलिस की प्रतिक्रिया (रेस्पॉंस) और धार्मिक अवसरों पर आयोजित जुलूस किस प्रकार नफरत भड़काने के रंगमंच बने, आदि को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट के संपादक वरिष्ठ एडवोकेट सी.यू. सिंह ने लिखा है कि ''अन्य किसी कारण के मुकाबले धार्मिक जुलूस बार–बार और व्यापक स्तर पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच दंगों का कारण बनते हैं।

रिपोर्ट में ''ये धार्मिक जुलूस रास्ते से गुजरते समय जिस तेजी से नफरत को हवा देते हैं उसका और उससे निपटने में पुलिस की ''बुजदिली और घटियापन'' का जिक्र किया गया।

अपने समापन में रिपोर्ट कहती है:

''उपलब्ध सबूत सिविल सोसायटी ग्रुपों, वकीलों, एकेडमिशियनों और एक्टिविस्टों द्वारा दिए गए इन बयानों की सम्पुष्टि करते हैं कि भारत स्थायी हिंसा के एक दौर में पहुंच गया है।''

रिपोर्ट में 100 सेवानिवृत्त उच्च–अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे उस पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ''कानून का प्रशासन वह तरीका बन गया है जिसके जरिये अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों, को स्थायी डर की एक ऐसी स्थिति में रखा जा सकता है''।

भाजपा का एक अन्य मुस्लिम विरोधी कदम

भजापा की समझ एवं नीति है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरूद्ध कदम उठाने से बहुसंख्यक हिंदू उसके पक्ष में आ जाएंगे। यह मतदाताओं के धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की नीति है। इसी रणनीति के अनुसार, कर्नाटक विधानसभा के अगले दिनों में होने वाले चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों में कैटेगरी 2बी के अंतर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए मिलने वाले 4 प्रतिशत के आरक्षण को समाप्त कर दिया है और इस चार प्रतिशत आरक्षण को नवगठित दो कैटेगरियों–2सी एवं 2 डी के अन्तर्गत कर्नाटक के दो प्रमुख हिन्दू समुदाओं–वोक्कालिग्गा एवं वीरशैवा लिंगायत को (प्रत्येक को दो–दो प्रतिशत) दिया है। इससे वोक्कालिग्गा का आरक्षण 4 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत और वीरशैवा लिंगायत का 5 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया है।

अल्पसंख्यकों के विरूद्ध यह कदम अत्यंत अमानवीय और शर्मनाक है। देश के लोग भाजपा सरकारों द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की ज्यादतियों को कब तक रहन करते रहेंगे?

प्रधानमंत्री जब ''सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'' का नारा देते हैं तो क्या उस ''सब'' में भारत के मुसलमान शामिल नहीं हैं?

अक्सर वह यह भी दोहराते रहते हैं ''वसुधैव कुटुम्बकम'' अर्थात पूरी दुनिया एक कुटुम्ब है। पर भाजपा मुसलमानों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है उससे तो लगता है कि उनके ''वसुधैव कुटुम्बकम'' का अर्थ है ''वसुधैव कुटुम्बकम, पर मुसलमानों को छोड़कर''।

आरक्षण में घात

यों तो मोदी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के हितों के बारे में बड़े दावे करती रहती है परंतु वास्तव में वह समाज के इन तबकों को नुकसान पहुंचाने के किसी भी अवसर से नही चूकती। यहां तक कि वह सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में इन तबकों के लिए आरक्षण के कानूनी प्रावधान में भी घात करती है।

उदाहरण के लिए, पिछले 5 साल में सिविल सर्विस के टॉप रैंक में आरक्षित श्रेणी में सिर्फ 27.37% नियुक्तियां हुई हैं, जबकि रिजर्वेशन कोटा 49.5% है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि आईएएस, आईपीएस और वन सेवा में पिछले 5 सालों में 4365 नियुक्तियां हुई। इसमें 334 अनुसूचित जाति, 166 अनुसूचित जनजाति और 695 पिछड़ी जातियों से हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता का क्षरण लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी

नई दिल्ली में 22 मार्च 2023 को रामनाथन गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान के 16वें संस्करण में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए अलग–अलग विचारों का सम्मान करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जब कहा कि ''असहमति को घृणा में नहीं बदलना चाहिए और नफरत को हिंसा में तब्दील नहीं होने देना चाहिए'' तो वह हवा में बात नहीं कर रहे थे, भारत के मौजूदा हालात की पृष्ठभूमि में बात कर रहे थे। भारत में आज जो कुछ हो रहा है उसी की बात कर रहे थे और कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके कथन में निहित थ कि आज असहमति और विरोध को कुचला जा रहा है, और यह नहीं होना चाहिए।

मीडिया को राज्य की अवधारणा में चौथा स्तंभ बताते हुए जब उन्होंने लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का एक अभिन्न घटक है और एक कार्यात्मक एवं स्वस्थ लोकतंत्र को एक ऐसी संस्था के रूप में पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना चाहिए जो सत्ता प्रतिष्ठान से कठिन प्रश्न पूछ सके, या जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है ''सत्ता से सच बोले'', तो वह कोई ''अप्रासंगिक'' या ''अमूर्त'' बात नहीं कह रहे थे। वह मोदी सरकार के अन्तर्गत प्रेस की स्वतंत्रता के काफी हद तक क्षरण और तद्जन्य लोकतंत्र के क्षरण की पृष्ठभूमि में यह बात कह रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब प्रेस को सत्ता प्रतिष्ठान से कठिन प्रश्न पूछने से रोका जाता है तो वह किसी भी लोकतंत्र की जीवन्तता से समझौता होता है। अगर किसी देश को लोकतंत्र में बने रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना होगा।

उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पत्रकारिता सच्चाई की किरण है जो हमें बेहतर कल की ओर जा सकती है। यह इंजन है जो सच्चाई, न्याय और समानता की खोज के आधार पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। डिजिटल युग की चुनौतयों के दौर में पत्रकारों के लिए अपनी रिपोर्टिंग में सटीकता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के मानकों को बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''भारत में समाचार पत्रों की एक महान विरासत है जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में काम किया है''।

इस अवसर पर 'द इंडियन एक्सप्रेस' समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका ने कहा, 'एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र के अविभाज्य अंग हैं और रहेंगे।'' क्या वह भी देश में

शेष पेज 10 पर...

भाजपा के सत्ता में आने के बाद महिलाओं पर बढ़े अत्याचार

राम नरसिम्हा राव

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हैदराबाद के राजबहादुर गौड़ हॉल में धर्मनिरपेक्षता बचाओ विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। एनएफआईडब्ल्यू की राज्य इकाइयों और वर्किंग वीमेन फोरम के तत्वावधान में कन्वेंशन आयोजित किया गया था। मुख्य भाषण प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रमा मेलकोटे ने दिया। एनएफआईडब्ल्यू की राष्ट्रीय सचिव डॉ. के रजनी मुख्य अतिथि थीं। पस्या पद्मा, प्रेम पावनी, नेदुनूरी ज्योति, उस्ताला सृजना, बी छाया देवी, मांदा सदालक्ष्मी, करुणा कुमारी, कमला रेड्डी, पडाला नलिनी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

डॉ. के रजनी ने ध्वजारोहण किया।

हनमकोंडा कोंडा और वारंगल में, ज्योति, सदालक्ष्मी, सुरजना, मल्लेश्वरी, सूर्यापेट में, लता देवी और पोटू कलावती, खम्मम में, नलिनी आदिलाबाद में, फातिमिद्स रंगारेड्डी जिले में, बंदी जंगम्मा भोंगीर में, मुन्ना लक्ष्मी, कोठागुडेम में, कोरीमी सुगुना भूपालपल्ली में, सुगुनम्मा, जनगामा में, महबूबाबाद में संबलक्ष्मी आदि ने सभाओं को संबोधित किया।

प्रो रमा मेलकोटे ने संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान शासक वर्ग ने कारपोरेट ताकतों को आर्थिक वर्चस्व सौंप दिया है, तानाशाही धीरे–धीरे बढ़ रही है और देश से कल्याणकारी उपाय धीरे–धीरे गायब हो रहे हैं क्योंकि शासक वर्ग कल्याणकारी बजट को कम किया जा रहा है। उन्होंने बहुसंख्यक आबादी को खुश करने की राजनीति करने वाली ताकतों को हराने की भी अपील की है। सरकारी कदमों की तारीफ करने वालों को सरकार देशभक्त और आलोचना करने वालों को देशद्रोही मान रही है। साम्प्रदायिक कट्टरवादी साम्प्रदायिक आधार पर भारतीय जनता का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि क्षेत्रीय दल समाजवाद की ओर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। महिलाओं को जुझारू जन संघर्ष शुरू करना चाहिए। समाजवाद संघर्षों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

पस्य पद्मा राज्य भाकपा सचिवमंडल सदस्य ने संबोधित करते हुए कहा है कि कई देश महिलाओं को नौकरी से निकाल रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस अपनी सत्ता की सीट की रक्षा के लिए धर्म का फायदा उठा रहे हैं और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। यह धीरे–धीरे गरीबों की सब्सिडी कम कर रहे हैं। सरकार अंधविश्वास की ओर महिलाओं का ध्यान भटका रही है इसलिए महिलाओं को जुझारू संघर्षों को संगठित करना चाहिए।

एनएफआईडब्ल्यू की राष्ट्रीय सचिव डॉ. रजनी ने संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति की विफलता के कारण मेडिकल छात्र आत्महत्या का सहारा ले रहे हैं और संस्थान रैगिंग को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल हैं। भाजपा सरकार संविधान को बदलने और मनुस्मृति लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

कन्वेंशन की अध्यक्षता वर्किंग वीमेन फोरम की राज्य अध्यक्ष प्रेम पावनी और एनएफआईडब्ल्यू अध्यक्ष यू सजृना ने की।

एनएफआईडब्ल्यू की तेलंगाना राज्य महासचिव एन ज्योति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रेरणा से महिलाओं के आंदोलनों को तेज किया जाना चाहिए। वह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हनमकोंडा में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। जनसभा से पूर्व अशोका जंक्शन से पब्लिक गार्डन तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। बैठक की अध्यक्षता मनचला रमादेवी जिला महासचिव एनएफआईडब्ल्यू ने की। ज्योति ने आगे संबोधित करते हुए कहा है कि शासक वर्ग भले ही इस देश में विकास की शेखी बघार रहे हैं, लेकिन महिलाओं में ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व और मनुवाद की भावना भरी जा रही है और उन्हें रसोई तक सीमित कर दिया गया है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कामकाजी महिलाओं की लड़ाई की भावना का प्रतीक है। लेकिन इस दिन को सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित करके विकृत और नीचा दिखाया जा रहा है। उन्हें गुलाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। भाजपा के सत्ता में आने के बाद महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। भाजपा शासित राज्यों में अपराध दर सूची में शीर्ष पर है। मोदी का "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" का नारा सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है। कानून कितने भी बन रहे हैं लेकिन क्रियान्वयन में ईमानदारी नहीं है। शराब सड़कों पर बह रही है और इसे पीकर कई लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध का सहारा ले रहे हैं। कई टीवी धारावाहिकों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।

सभा को राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष एम सदालक्ष्मी, आर दीना, यास्मीन, राजिता, उमा, तिरूमाला, ललिजा आदि ने भी संबोधित किया।

आन्ध्र प्रदेश

मोदी के सत्ता में आने के बाद, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है और महिलाओं पर अत्याचार दिन–ब–दिन बढ़ रहे हैं", एनएफआईडब्ल्यू की राष्ट्रीय नेता अक्किनेनी वनजा ने जोर देकर कहा। वे बुधवार को कुक्कुनूर मंडल के श्रीनिवास फंक्शन हॉल में एक सभा को संबोधित कर रही थीं. बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वर्का श्यामला ने की।

उन्होंने आगे संबोधित करते हुए कहा कि मोदी राज में महिलाओं पर यौन हमले, बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न में वृद्धि हुई है। यह दोषियों के प्रति भाजपा सरकार की नरमी का नतीजा है। पूरे देश में महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। यद्यपि महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस उन्हें मनुवाद और हिंदू धर्म की मदद से अकेले रसोई तक ही सीमित रखना चाहते हैं। 113 साल पहले अमेरिका, जापान और जर्मनी के पूंजीपति महिला कर्मचारियों से 14 से 16 घंटे काम ले रहे थे। महिलाओं ने 10 घंटे कार्य दिवस के लिए जुझारू लड़ाई लड़ी, महिलाएं अपने मिशन में सफल रहीं और 10 घंटे कार्य दिवस हासिल किया और तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। गुजरात में बिलकिस बानो का यौन उत्पीड़न किया गया और उसके परिवार के 13 सदस्यों की जघन्य हत्या कर दी गई। राज्य सरकार ने उन दोषियों को रिहा कर दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा पोडू भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। वे आदिवासी महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं और महिलाओं पर कई तरह के अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के गैरजिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ महिलाओं को संघर्ष करना होगा। महिलाएं भी सभी विधायी निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर एकजुट आंदोलन चलाती हैं।

मन्नान के कृष्ण चैतन्य ने संबोधित करते हुए कहा है कि यद्यपि 113 वर्षों के दमन के प्रतिरोध के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, फिर भी शोषण नहीं रोका जा रहा है और महिलाएं सशक्तिकरण प्राप्त नहीं कर सकी हैं। 75 साल पहले आजादी मिलने के बाद भी महिलाओं को पानी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कई गांवों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं आम लोगों की पहुंच में नहीं हैं। इसलिए महिलाओं से संबंधित मांगों के लिए महिलाओं को अनवरत संघर्ष करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भावना के साथ।

मीटिंग को संबोधित करने वालों में कोंडेती बेबी, वर्षा लक्ष्मी, एस वनकन्ना, के जयश्री, एस सरोजा, वर्षा रोजा, वी गंगा आदि भी शामिल थीं।

कुछ सामयिक मुद्दे और ...

पेज 9 से जारी...

आज प्रेस की स्वतंत्रता के भारी क्षरण और उस कारण लोकतंत्र के लिए पैदा हुए खतरे का परोक्ष रूप से जिक्र नहीं कर रहे थे?

प्रधान न्यायाधीश का धन्यवाद करते हुए 'द इंडियन एक्सप्रेस' के संपादक राजकमल झा ने कहा: ''स्वतंत्र प्रेस के लिए आपके दृष्टिकोण और चेतावनियों से हमारा यह भरोसा पुख्ता होता है कि सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए ध्रुवतारा बना रहेगा''। उन्होंने कहा, ''साल दर साल, एक के बाद एक मामले में उस ध्रुवतारे ने आगे की राह को रोशन किया है और अदालतें हमारी आजादी को विस्तारित करने के लिए सत्ता पर दबाव बनाती रही हैं''।

उन्होंने कहा, ''यही कारण है कि जब रोशनी मंद होती है....जब एक रिपोर्टर को आतंकवादियों के लिए बने कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अन्य किसी को कार्टून साझा करने के लिए एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भाषण के लिए एक कॉलेज छात्र, एक टिप्पणी के लिए एक अभिनेता को जेल में डाल दिया जाता है, या जब किसी खबर का रिजोएंडर पुलिस एफआईआर के रूप में आता हैं, तब हम ध्रुवतारे की ओर इसकी दिशा दिखाने वाली रोशनी के लिए रुख करते हैं''।

जाहिर है 'द इंडियन एक्सप्रेस' के सम्पादक मोदी सरकार द्वारा स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए जा रहे हमले का स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर रहे थे।

प्रेस की स्वतंत्रता का किस हद तक क्षरण हो गया है और प्रेस पर कितना दबाव है, इसे हाल के घटनाक्रम से बखूबी समझा जा सकता है। हिन्डनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद चंद सम्मानीय अपवादों को छोड़ भारत के तमाम मीडिया को मानो सांप सूंघ गया है। किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि अडानी कारपोरेट घराने को मोदी सरकार जिस तरह नाजायज फायदे पहुंचाती रही है और हिन्डनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह उसे बचाने की कोशिश कर रही है, इस संबंध में कुछ लिख सके।

संसद में विपक्ष मांग कर रहा है कि मामले की तह में जाने के लिए जरूरी है कि एक संसदीय समिति पूरे मामले की जांच करे। सरकार इस जांच से भाग रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इंगलैंड में दिए गए भाषणों का बहाना बनाकर हिन्डनबर्ग रिपोर्ट से अडानी कारपोरेट घराने की धोखाधाड़ी और अनियमितताओं और सरकार के सर्वोच्च स्तर की उसके साथ मिलीभगत के आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और स्वयं सरकार ही संसद को नहीं चलने दे रही। चंद सम्मानीय अपवादों को छोड़ भारत का मीडिया–समाचारपत्र और टेलीविजन चैनल–सरकार के इस रवैये की भर्त्सना करने के बजाय सरकार का पक्षपोषण करने की कोशिश कर रहा है। देश के सभी बड़े माने जाने वाले समाचार पत्रों के पिछले एक महीने के संपादकीयों पर नजर डाल लें, पता लग जाता कि जिसे मुख्य धारा मीडिया कहा जाता है, वह क्या कर रहा है। वह अडानी रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुख्य प्रश्न कि मोदी और अडानी के बीच क्या सम्बंध है और विपक्ष के इस आरोप के सम्बंध में खामोशी बरत रहा है कि मोदी सरकार के दौरान अडानी कारपोरेट घराने को नाजायज फायदे पहुंचाए गए हैं। स्वतंत्र प्रेस का कर्तव्य था कि प्रेस स्वयं इन प्रश्नों को उठाता। ऐसा करने के बजाय भारत के मीडिया का बड़ा हिस्सा मोदी सरकार के प्रचार दस्ते में बदल रहा है।

मीडिया और स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता का यह क्षरण भारत के लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है।

आन्ध्र प्रदेश भाकपा की राज्य परिषद बैठक

राम नरसिम्हा राव

मोदी नीत भाजपा के नेतृत्व में देश इस कदर प्रतिगामी राह पर चल पड़ा है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार की जनविरोधी और कारपोरेट समर्थक नीतियों को उजागर करने का यह सही समय है। इसी के मद्देनजर भाकपा ने इस वर्ष 14 अप्रैल से 15 मई तक पूरे देश में पदयात्राएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। यदि आवश्यक हो तो सभी गांवों में 'मोदी हटाओ– देश बचाओ' नारे के तहत अभियान चलाया जाए। हमें तानाशाही शासन को उजागर करके और लोगों को जगाकर मोदी सरकार को हटाने के लिए अपने सभी प्रयास करने चाहिए, डॉ. के नारायण, राष्ट्रीय सचिव, भाकपा ने यह बातें कही। वह शुक्रवार से दासरी भवन, विजयवाड़ा में दो दिवसीय आंध्रप्रदेश की भाकपा राज्य परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता भाकपा के राज्य सचिवमंडल सदस्य पी रामचंद्रैया ने की। जेवीएस मूर्ति राज्य के सहायक सचिव, भाकपा ने शोक प्रस्ताव पेश किया। एम नागेश्वर राव भाकपा के राज्य सह सचिव ने भी अपनी बात रखी।

डॉ. के नारायण ने मुख्य अतिथि के रूप में आगे संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता पर काबिज होते ही भाकपा ने मोदी की पहचान एक खतरनाक ताकत के रूप में कर ली थी। वर्तमान में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक, और जांच ब्यूरो आदि जैसे बहुत ही संवैधानिक निकायों को भी खतरे में डाल दिया है। इन संवैधानिक निकायों को उनकी पॉकेट संस्था बना दिया गया है। 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल अडानी को मोदी हर संभव मदद कर रहे हैं। वह इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने की 16 विपक्षी पार्टियों की मांग को टाल कर समय की बर्बादी कर रहे हैं। उनके तानाशाही कदम का ताजा उदाहरण राहुल को सलाखों के पीछे भेजे की योजना और राहुल को संसद सदस्य रहने से अयोग्य घोषित करना है।

यह और कुछ नहीं विपक्ष के प्रति बदले की राजनीति की भावना है। जबकि मोदी सांप्रदायिक एजेंडे को लागू कर रहे हैं, देश की संपत्ति और दौलत को कारपोरेट क्षेत्र को सौंप रहे हैं और इस प्रकार पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। जैसे–जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा फिर से खालिस्तान आंदोलन को सामने रख कर राष्ट्रीय भावना पैदा कर रही है। हालांकि सभी बंदरगाह अडानी को सौंपे जा रहे हैं, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना अनिवार्य है, जो सामान्य रूप से लोगों की आवाज और विशेष रूप से असहमति का गला घोंट रही है। बीजेपी और वाईएसआरसीपी दोनों एक ही हैं, इसलिए दोनों केंद्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों पर चुप हैं। सीपीआई हमारे देश, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की रक्षा के लिए सबसे आगे रहने वाली है। भाकपा के द्वारा भाजपा के खिलाफ सभी समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है।

भाकपा के राज्य सचिव के रामकृष्णा ने राज्य में राजनीतिक स्थिति, अतीत की गतिविधियों और भविष्य की कार्रवाई के कार्यक्रम पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। राज्य में हाल ही में एमएलसी चुनावों पर रिपोर्ट देते हुए अपनी हार के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि वाईएसआरसीपी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, हालांकि वह सभी तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं जैसे गैर स्नातकों और निरक्षरों को भी स्नातक के रूप में नामांकित करना। चुनाव जीतने के लिए पैसे, बाहुबल और प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चुनाव जीतने में बुरी तरह नाकाम रहे। मोदी द्वारा अडानी को संपत्ति सौंपने पर जगन नहीं बोलेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस मामले पर अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? और राहुल को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने पर भी वह खामोश ही हैं।

रामकृष्णा ने पोलावरम परियोजना पर संबोधित करते हुए कहा कि इसका निर्माण 130 फीट के बजाय 150 फीट की ऊंचाई के साथ किया जाना चाहिए, जैसा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उद्घाटन के समय वादा किया था। इससे उत्तरांध्र और रायलसीमा के लोगों को पानी मुहैया कराया जा सकेगा अगर इसे 150 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाए। उसी के आधार पर जलमग्न गांवों के लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। दो गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएंगी जिनमें से एक 29 अप्रैल को अनंतपुर में और दूसरी 28 अप्रैल को विजाग में आयोजित की जाएगी। इस मुद्दे पर 27 व 28 अप्रैल को सभी जिला कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल की जायेगी. हालांकि भारी बारिश के कारण 3 लाख एकड़ की फसल खराब हो गई, लेकिन जगन इस कहर पर चुप हैं। आंध्र प्रदेश की भाकपा और एआईकेएस इकाइयां क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगी और भारी नुकसान का आकलन कर राज्य और केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएंगी। उन्होंने पूछा कि शादी का कार्ड देने के नाम पर अडानी और जगन के बीच क्या बातचीत हुई इसको सामने आना चाहिए।

भाविष्य के कार्यक्र नपर बालतु हुए रामकृष्णा ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक सामन विचारों वाली पार्टियों के बीच प्रचार अभियान 14 अप्रैल से 15 मई के बीच चलाया जायेगा।

मंच पर भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अक्कीनेनी वनजा, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावुला वेंकैया, भाकपा के राज्य सचिवमंडल सदस्य जल्ली विल्सन, किसान सभा के महासचिव केवीएस प्रसाद शामिल थे।

शहीद–ए–आजम भगत सिंह को याद किया गया

इलाहाबादः ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एवं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज शहीद दिवस का आयोजन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में किया गया। क्रांतिकारी शहीद–ए–आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महानायक के इस पावन शहीदी दिवस पर युवाओं और छात्रों का जोश देखने लायक था।

उत्तर प्रदेश में छात्रों नौजवानों का संयुक्त आयोजन बहुत ही सफल रहा एवं कई वर्षों बाद ही हुआ। इस आयोजन में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी सुखजिंदर माहेसरी, यूथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष शांति महेंद्र पाल एवं प्रदेश सचिव साथी अमजद शाह की मौजूदगी रही। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव अरविंद राज स्वरूप, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष साथी संजय सिंह, प्रदेश सचिव साथी मुजम्मिल, साथी सुफियान, साथी नोमान खान, साथी जितेंद्र आर्य के साथ–साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम छात्र अन्य सभी जिला विद्यालय, विश्वविद्यालय के साथी मथुरा के साथी रवि भी मौजूद रहे।

उक्त कार्यक्रम द्वारा छात्रों ने नौजवानों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि हम शहीदे आजम भगत सिंह के विचारों को प्रदेश के कोने–कोने तक ले जाकर छात्रों और युवाओं में एक नई क्रांतिकारी उर्जा का सृजन करेंगे। देश की केंद्रीय सत्ता एवं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जिस प्रकार छात्रों एवं युवाओं के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है वह बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। विश्वविद्यालय जिस प्रकार अपनी मनमानी फीस वृद्धि करके, मनमाना वातावरण बना रहा है। जोकि छात्रों के प्रगतिशील आंदोलनों को कुचलने की मुहिम की तरह चलते हुए दिख रहा है। नौजवानों को दो करोड़ सालाना नौकरी का झांसा देकर सत्ता में आने वाली सरकार एक भी रोजगार देने में सक्षम नहीं है। सभी सरकारी महकमों में लाखों की संख्या में रिक्त पद आज भी खाली हैं और अग्निपथ जैसी रोजगार योजना देखकर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेतृत्वकारी साथियों ने यह निर्णय लिया है कि छात्र और युवाओं को जगाने की जिम्मेदारी हमारी है और इसी क्रम में छात्र युवा दोनों मिलकर पूरे देश में प्रदेश में इसी प्रकार के कार्यक्रम में लगे रहेंगे जब तक की सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी ना हो जाए।

रोशन कुमार सिन्हा की रिहाई को लेकर बिहार निवास पर प्रदर्शन

एआईवाईएफ के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के राज्य सचिव रोशन कुमार सिन्हा को अग्निपथ योजना के विरोध में चले आंदोलन के नाम पर झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार कर 16 मार्च को जेल भेज दिया गया।

अग्निपथ योजना एक विनाशकारी योजना है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को धोखा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना है। हालाँकि, एआईवायएफ और उसके साथी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति प्रदर्शित करते हैं। अग्निपथ के विरोध में हिंसा से संबंधित मनगढ़ंत मामलों के तहत रोशन कुमार सिन्हा को गिरफ्तार करना विरोध की लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है और शासन की आलोचना करने वालों के बीच भय पैदा करने के लिए एक सोची समझी चाल है।

उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए एआईवायएफ ने 27 मार्च 2023 (सोमवार) को दिल्ली में बिहार भवन चलो का आयोजन किया। आयोजन की अध्यक्षता शशि कुमार गौतम ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजिंदर महेसरी, महासचिव थिरुमलाई रमन, एआईएसएफ के महासचिव विक्की महेसरी और अन्य लोगों ने आंदोलन में भाग लिया और रोशन कुमार सिन्हा की रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। एआईवाईएफ के पूर्व महासचिव संतोष कुमार, एमपी ने हिरासत में लिए गए साथियों से मुलाकात की।

रोशन कुमार सिन्हा की रिहाई को लेकर भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे केरल, बिहार, तेलंगाना में प्रदर्शनों के आयोजन किये गये।

आन्ध्र प्रदेश में वामपंथी दलों का ''चलो विधानसभा मार्च''

भाकपा ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और बर्बरता की निन्दा की

राम नरसिम्हा राव

भाकपा और भाकपा (मा) की राज्य परिषदों, अन्य राजनीतिक दलों और जन संगठनों द्वारा किए गए आह्वान के जवाब में, शासनादेश संख्या 1 के विरोध में चलो विधानसभा का आयोजन किया गया। शासनादेश का उद्देश्य लोकतांत्रिक आवाज और असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटकर विपक्ष की आवाज को दबाना है।

विधानसभा के पास भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था और विजयवाड़ा की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ट्रेनों, बसों, ट्रकों, वाहनों आदि में गिरफ्तार किया। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। कई को उनके संबंधित जिलों में हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के दमनकारी तरीकों के बावजूद, प्रदर्शनकारी भाकपा के राज्य मुख्यालय दासरी भवन तक पहुँच सके। प्रदर्शनकारियों ने तुम्मलापल्ली कलाक्षेत्र में एक रैली निकाली जहां नेताओं ने डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।

भाकपा आन्ध्र राज्य सचिव के. रामकृष्णा ने संबोधित करते हुए मांग की कि वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा लाया गया लोकतांत्रिक विरोधी शासनादेश संख्या–1 जो संविधान में निहित लोकतांत्रिक मौलिक अधिकारों से इनकार करता है, उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। बैठक को वी श्रीनिवास राव, राज्य सचिव, सीपीएम, वाईवीराव, राज्य सचिवमंडल सदस्य, सीपीएम, अक्किनेनी वनजा, भाकपा केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य, मुप्पल्ला नागेश्वर राव, भाकपा राज्य सहायक सचिव ने भी संबोधित किया। जुलूस में जी ईश्वरैया, राज्य सचिवमंडल सदस्य डी शंकर राज्य कार्यकारी सदस्य, भाकपा, जी कोटेश्वर राव विजयवाड़ा शहर सचिव, भाकपा, पेनुमत्सा दुर्गा भवानी राज्य महासचिव, एनएफआईडब्ल्यू, एआईवाईएफ के नेता और जॉनसन बाबू और शिवा रेड्डी राज्य अध्यक्ष और महासचिव, राज्य एआईएसएफ, पंचदारला दुर्गाम्बा और ओरसू भारती, एनएफआईडब्ल्यू, नक्का वीरभद्र राव भाकपा शहर सहायक सचिव ने भाग लिया।

पेनामालूरू पुलिस ने पूर्व एमएलसी जल्ली विल्सन को उनके घर से एक दिन पहले शाम को गिरफ्तार कर लिया था। जी ओबेलेसू को रविवार को ही घर पर नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने मांग की कि शासनादेश को वापस लिया जाए और उसे वापस लिये जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।

पूर्व गृह मंत्री, निम्मकयाला चिना राजप्पा, गदर राम मोहन राव, विजयवाड़ा पूर्व के टीडीपी विधायक बंडारू सत्यनारायण मूर्ति ने कृष्णालंका पुलिस स्टेशन का दौरा किया और सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और कांग्रेस

शेष पेज 15 पर...

बंटवारे के समय के वादे पूरे करवाने के लिए भाकपा की पदयात्रा

मोदी के शासन से लोकतंत्र और संविधान को खतरा

टी श्रीनिवास राव

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरएसएस द्वारा तराशी गई कठपुतली हैं और संघ परिवार के दर्शन को लागू करते हुए देश पर शासन कर रहे हैं। उक्त बातें भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ. के. नारायण ने कही। वे रविवार को महबूबाबाद शहर के मुत्यालम्मागुड़ी केंद्र में मुख्य वक्ता के रूप में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पदयात्रा के दूसरे दिन पदयात्रा कुरवी महमूदाबाद पहुंची थी। भाकपा द्वारा राज्य के विभाजन के समय दिए गए आश्वासनों को लागू करने और बय्याराम में स्टील प्लांट, काजीपेट में कोच फैक्ट्री, मुलुगु में आदिवासी विश्वविद्यालय आदि की मांगों को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया था।

नारायण ने आगे संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं, हालांकि उन्होंने गुजरात में नरसंहार किया और देश के प्रधानमंत्री बन गये। उनके शासन से हमारे भारतीय संविधान को खतरा है। इसलिए इस देश के लोगों पर एक मंच पर एकजुट होकर अपने संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। नारायणा ने नाराजगी जाहिर की कि गैर–बीजेपी शासित राज्यों में आरएसएस के नेताओं को राज्यपाल नियुक्त कर उन राज्यों में अराजकता पैदा की जा रही है और उन विधानसभाओं में पारित कई विधेयकों को बिना मुहर लगाए दबाया जा रहा है। नारायण ने यह भी साफ किया कि भाकपा राज्य के बंटवारे के समय दिए गए आश्वासनों के लागू होने तक संघर्ष जारी रखेगी। आश्वासनों के क्रियान्वयन

शेष पेज 15 पर...

आज जो इप्टा कर रही है, मुझे उससे बहुत उम्मीद है

गौहर रजा

(झारखंड के मेदिनीनगर (डालटनगंज) में 17, 18 और 19 मार्च को इप्टा की 15वीं नेशनल कांफ्रेंस के उद्घाटन सत्र में वैज्ञानिक, शायर गौहर रजा का वक्तव्य।)

दोस्तो, अभी साथियों ने और खासतौर से हमारे देश के सबसे बड़े डायरेक्टर, राइटर–लेखक प्रसन्ना जी ने आपके सामने यह बात रखी कि हम बहुत बुरे और खराब दौर से गुजर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम खराब दौर से गुजर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है?, इसका मतलब होता है, जैसा उन्होंने कहा कि गरीबी और ज्यादा बढ़ती जाए, और अमीरी और ज्यादा बढ़ती जाए। इनके दोनों के बीच की खाई बढ़ती जाए। बल्कि खाली इससे खराब दौर शुरू हो जाता है। यह खराब दौर है, जाहिर है। उस पीरियड में जब कोरोना से इंसानियत की सांसें रुकती हुई दिखाई दे रही थीं, तब लूट का बाजार गर्म था। हमारे देश के तीन–चार घराने जेब भर रहे थे, जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही थी, तो उनका प्रोफिट लगातार बढ़ता जा रहा था। और सिर्फ एक–दो–तीन–चार–पांच गुना नहीं, कई सौ गुना, इस बीच में दो साल में बढ़ा है। ये बात बताती है कि लूट के बाजार में कोई कमी नहीं आई, जब लोग ऑक्सीजन के लिए और दवाओं के लिए तरस गए। जब इस मुल्क के ऊपर एक दम से दो–तीन घंटे के नोटिस के ऊपर लॉकडाउन लगा दिया गया। पर इससे खाली बुरा दौर शुरू नहीं होता। बुरा दौर तब शुरू होता है, जब हमारे देश के उस ढांचे को जो सत्तर सालों में तैयार किया गया, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। हमारी ज्यूडिसरी का जो हाल हुआ, हमारे न्यायालय का जो हाल हुआ है, वो हमारे सामने है।

हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं, उन्होंने आगे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है कि क्या कल हमारे देश में पढ़ी–लिखी नस्लें पैदा होंगी? और क्या गरीब आदमी अपने बच्चों को आगे तक पढ़ा पाएगा? हमारे देश के अंदर जब मीडिया के ऊपर भयानक अटैक होता है, और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है, तब शुरू होता है, बुरा दौर। आपको ये मालूम है कि सिवाय मोदी–मोदी–मोदी, सुबह से लेकर शाम तक और उसके साथ–साथ हिंदू–मुसलमान, हिंदू–सिख वगैरह–वगैरह। नफरत का बाजार। कुछ ऐसा लगता है कि टेलीविजन से घर के अंदर नफरत बह के आ रही है। तब शुरू होता है, बुरा दौर देश के अंदर। जब हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक होता है, वैज्ञानिकों पर अटैक होता है और उनके स्कॉलरशिप बंद कर दिए जाते हैं। ग्रांट बंद कर दी जाती है, यह कहकर कि अब इस देश में पंचगव्य के ऊपर यानी गाय के पेशाब के ऊपर, गोबर के ऊपर और उसके जो प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी। बजाय इसके कि हमारे यंग साइंटिस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज साइंस के बारे में बात करें। आपको और मुझे, मीडिया ये नहीं बताएगा कि साइंस के ऊपर और विज्ञान के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ है। मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं जानता हूं कि अंदर घुस कर के इसरो से ये कहा जा रहा है कि शास्त्रों में से निकालो और ये देखो कि आकाश का क्या मतलब होता है? ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों के लिए जो आकाश को रोज छू रहे हैं, उनसे ये कहा जाए कि तुम शास्त्रों में से निकालकर कि अब आकाश के बारे में रिसर्च करो।

दोस्तो, मैं ये समझता हूं कि ये आगे आने वाली नस्लों के लिए इसलिए भयानक होने जा रहा है कि जब हमने अंग्रेजों से सत्ता ली और इस देश को संभाला था, तो हम बहुत गरीब थे। अंग्रेजों के आने से पहले यानी मुगलों का दौर, बहुत बुरा दौर था। मैं सारे राजाओं के दौर को बहुत बुरा दौर मानता हूँ। लेकिन उस वक्त ये देश दुनिया की एक चौथाई दौलत पैदा कर रहा था। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, जब अंग्रेजों ने यहां कदम रखे। और उन्होंने कदम भी इसलिए रखे। उन्होंने अफ्रीका को भी इसलिए कैप्चर किया था कि वो हिंदुस्तान तक आना चाहते थे। और उन्होंने जब इस देश को छोड़ा है, तो एक प्रतिशत से भी कम दौलत पैदा कर रहा था। यानी सब कुछ लूट कर के अंग्रेज इस देश से ले गए थे। और तब हमने ये सोचा था कि हम इस देश का आधार साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर रखेंगे। साइंटिफिक टेम्पर पर रखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं?, वो ये कहते हैं कि गणेश जी जो हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर के, बिना तैयारी के, बेशर्मी के साथ ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बता पाते। इस देश ने दुनिया को जीरो दिया है और मैथमेटिक्स में हम सबसे आगे हैं। बिना तैयारी के वो जाते हैं और इस देश को बेइज्जत करते हैं, जब वो अंग्रेजी का एक छोटा सा शब्द, उसकी स्पेलिंग नहीं बता पाते। क्यूं कोशिश करते हैं?, वो प्रधानमंत्री हैं, इस देश का पूरा साइंटिफिक और बाकी यूनीवर्सिटी उनकी कमांड के ऊपर हैं, किसी से भी ठीक करवा सकते हैं, अपनी बातों को। लेकिन इस देश में आज वो लोग सत्ता में हैं, जो जिंदगी भर बाबाओं के पैर छूकर के जवान हुए हैं।

हमारे देश की आजादी की लड़ाई के वक्त जो लीडरशिप उभरी थी और जिसमें कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा हाथ था। वो पढ़ती थी, लिखती थी। वो बेहतरीन दिमागों के साथ रोज संवाद करती थी। सिर्फ अपने देश के बेहतरीन दिमाग नहीं, लेखक, बुद्धिजीवी, रंगकर्मी ये सब उनके चारों और हुआ करते थे। सिर्फ अपने देश के नहीं, बल्कि दुनिया भर में। हमें मालूम है कि किस तरह आइंस्टाइन और गांधी जी के बीच में संवाद होता था। हमें मालूम है कि नेहरू के आसपास किस तरह के लोग थे। हमें मालूम है कि कम्युनिस्ट जो थे, वो किस तरह की चीजें पढ़ा करते थे। आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा भयानक किस्म की लीडरशिप ने सत्ता हथिया ली है। इन्हें सिर्फ हिंसा आती है। और इसलिए इस देश में ये दौर, बुरा दौर है। खतरनाक दौर है। दोस्तो, क्वालिफिकेशन से नहीं होता, आज जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है कि वो दसवां पास हैं, वो इससे ज्यादा नहीं पढ़े हैं। इसके बावजूद और यूनीवर्सिटियों ने उनको अलग–अलग तरह की डिग्रियां दे दी हैं। अगर कोई अनपढ़ हो, मान लीजिए उसने यूनीवर्सिटी की डिग्री ली है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो प्रधानमंत्री हो सकता है और होना भी चाहिए शायद, अगर जनता उसे चुने। लेकिन जाहिल होना, ये भी न पता करना कि मैं किससे सीख सकता हूं, ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये देश के लिए खतरनाक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। दोस्तो, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए उनको गर्मी और सर्दी ज्यादा लगने लगती है। वो सरदी को कह पाते हैं, सर्दी नहीं बोल पाते। और वो बच्चों के सामने ये बात कह रहे होते हैं। और बच्चों से ये कह रहे होते हैं कि इस देश में सारे बच्चों को एग्जाम के वक्त मुश्किल सवाल पहले करना चाहिए और आसान सवाल बाद में करना चाहिए। हम सारे टीचर, बच्चों को लगातार ये बात सिखाते रहते हैं कि पहले आसान सवाल करो, फिर उसके बाद मुश्किल सवाल करो। ये खतरनाक है। और इसलिए खतरनाक है कि अगर कोई राह चलता आदमी इस तरह की बातें करे, तो कोई परेशानी की बात नहीं, हम उसे ठीक कर लेंगे। पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है, तो देश के अंदर नीचे तक ये मैसेज जाता है कि अब साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, पढ़ाई–लिखाई, जानना–जानकारी हासिल करना, खोजबीन करना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये देश अपने दिमाग से निकली कोई भी बेकार बात से चलेगा। और जब ये मैसेज जाता है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का भी स्ट्रक्चर चरमरा जाता है। जो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है।

हम इसलिए बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और इस दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो जैसा अभी कहा गया कि इसमें नौजवानों का क्या रोल होगा?, मुझे नौजवानों से बेहद उम्मीद है। और मुझे कला से बहुत उम्मीद है। आज जो इप्टा कर रही है, मुझे उससे बहुत उम्मीद है। इसलिए कि सबसे ज्यादा डर लगता है, ऐसे लोगों को कला से। सबसे ज्यादा डर लगता है, एक छोटी सी नज्म से। सबसे ज्यादा डर लगता है, एक छोटे से लेख से। सबसे ज्यादा डर लगता है, जिन्हें हम फासिस्ट कहते हैं, एक नाटक से। और वो इसलिए लगता है कि उन्हें मालूम है कि एक नाटक, एक नज्म, एक कविता हो या एक लेख हो, वो लोगों के दिमाग के ऊपर असर कर सकता है। वो लोगों को जोड़ सकता है। वो लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने का ख्वाब दिखा सकता है। वो ये कह सकता है कि हमें क्या चीजें बर्दाश्त नहीं है। और तब हमला शुरू होता है, देश के कलाकारों पर। मुझे इस बात का फख्र है कि जब ये सरकार 2014 के बाद आई, तो सबसे पहले हमारे कलाकार उठे थे और लगभग पांच सौ कलाकारों ने सिग्नेचर किए थे और अपने अवार्ड वापस किए थे। मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूं। ये बात जर्मनी में भी नहीं हो पाई, लेकिन हमारे देश के कलाकार, हमारे देश के बुद्धिजीवी सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने देश को चेताने की कोशिश की। उसके बाद तो जाहिर है कि और भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन सबसे आगे की रो में खड़े होने वाले थे, हमारे देश के कलाकार। और उन कलाकारों में से आज बहुत सारे कलाकार यहां जमा हैं, आपके सामने हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी। ये स्ट्रगल जारी रहेगी। और नई नस्लें लगातार इसमें शामिल होती रहेंगी।

(प्रस्तुतिः जाहिद खान)

इप्टा के इतिहास और निरंजन सेन की जिंदगानी पर नजर डालती किताब

'इप्टा की अनकही कहानियाँ' का विमोचन

डाल्टनगंजः झारखंड के डाल्टनगंज में आयोजित इप्टा की 15वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन यानी 17 मार्च को लेखक–पत्रकार जाहिद खान, मित्रा सेन मजूमदार और दिलीप चक्रवर्ती द्वारा संपादित किताब 'इप्टा की अनकही कहानियाँ' का विमोचन हुआ।

स्थानीय शिवाजी मैदान में आयोजित इप्टा राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में इप्टा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नाट्य आलोचक शमीक बंधोपाध्याय, वरिष्ठ रंगकर्मी नाटककार प्रसन्ना, वैज्ञानिक–कवि–संस्कृतिकर्मी गौहर रजा, पद्मश्री मधु मंसूरी, एन. बालचंद्रन, इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश वेदा, प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव सुखदेव सिंह सिरसा, इप्टा के राष्ट्रीय सह सचिव शैलेन्द्र कुमार, उपन्यासकार रणेन्द्र आदि ने इप्टा के इतिहास पर केंद्रित निरंजन सेन की इस महत्वपूर्ण किताब का विमोचन किया। किताब 'लोकमित्र प्रकाशन' नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है।

गौरतलब है कि निरंजन सेन, इप्टा के तीसरे राष्ट्रीय महासचिव थे। जिन्होंने 1946 से लेकर 1964 एक लंबे अंतराल तक इप्टा का नेतृत्व किया।

एक अकादमिक कसरत या हिन्दूराज...

पेज 3 से जारी...

हवा दी जा रही है। 150 साल बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नामाकरण एक दक्षिणपंथी आइड्लाग दीन दयाल उपाध्याय के नाम रख दिया गया। दिल्ली सहित कई भाजपा शासित प्रदेशों के भवनों, सड़कों के नाम मनमाने तरीके से लगातार बदले जा रहें हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की कहानी सर्वविदित है, और मोदी–योगी राज की दशा और दिशा खुद बयां करती है। सत्ता के भी कुछ लोग लंबे स्वर में सरकार के इस रवैए की आलोचना करते हैं, लेकिन अधिकांश इसे हिन्दुओं की विजय के रुप में प्रतिस्थापित करते हैं। इलाहाबाद जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली है और जो हिन्दू धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जिसे अकबर ने नाम दिया था, उसे बदल कर प्रयागराज किया गया है। इलाहाबाद मुगलों और ब्रिटिश काल में एक सांस्कृतिक और राजनीतिक हब रहा है। सरकार मुगल इतिहास को जनमानस से मिटाने की हरेक कोशिश में लगी है। कई राज्यों के विद्यालयों के पाठ्यक्रमों से मुगल और मुस्लिम इतिहास को पूरी तरह हटा दिया गया है। अठारहवीं सदी के दक्षिण भारतीय मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिन्हें महान शासक और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोधी माना जाता है, उन्हें भी पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया है। जब भारत की एक दो पीढ़ी इस तरह के मनगढ़ंत और हिन्दुवादी इतिहास पढ़ेगी तो धीरे धीरे सच की तरह कबूल कर लेगा और देश का माहौल कैसा होगा यह आज निश्चित रुप से चिंता का विषय है।

मूल और विवादास्पद सवाल यह है कि इतिहास का पुनर्लेखन केवल पूर्णतः अकादमिक कार्य है(?) या इसके पीछे संदेहास्पद उद्देश्य और इरादा है। यह सच है कि इतिहास का निष्कर्ष कभी अंतिम नहीं होता और इसका पुनर्लेखन नये तथ्यों के संदर्भ में अकादमिक ही है। सही और विश्वसनीय तथ्यों के आलोक में इतिहास के पुनर्लेखन पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इतिहास के पुनर्लेखन के समय इसमें सभी पक्षों को निष्पक्षता से समावेशित किया जाना चाहिए। इसमें अपने समझ और विचार के अनुकूल कुछ चुनिंदा को शामिल कर लिखना, और इसे इतिहास कहना ठीक नहीं है। यह इतिहास को भटकाने का कुत्सित प्रयास ही कहा जायेगा। पूर्व के इतिहासकारों को फिर से लिखने में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ऊपर उठकर निष्पक्षता पूर्वक तथ्यों के आधार पर लिखा जाये। यह पूर्णतः अकादमिक कार्य हो और अपने दर्शन और विचार के अनुकूलन के लिए मात्र न हो। इतिहास भावनाओं की अभिव्यक्ति हरगिज नहीं है और न ही जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर समाज को बांटने का हथियार है। इतिहास समाज को एकताबद्ध रखने और करने का सफल अस्त्र हो सकता है यदि इसे घृणा और कट्टरता के दृष्टिकोण से परे और खास वैचारिक प्रतिबद्धता की स्थापना के लिए न लिखा जाये। वर्तमान सरकार और सत्ता के इशारे पर नाचने वाले लोग आजकल हायतोबा इसलिए मचा रहे हैं कि वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी का ब्रेनवाश किया जाये ताकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में वे आगे बढ़ सके। अगर ऐसा हुआ तो भारत की बहुआयामी एकता के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसका हर स्तर पर तीव्र विरोध और निषेध अंतिम क्षण तक जरुरी है। हमारी स्पष्ट समझ है कि 'इतिहास बचाओ, भारत बचाओ' जैसे देशव्यापी अभियान चलाने की आज जरूरत है।

'धीरेंदु मजूमदार की माँ' नाटक का...

पेज 4 से जारी...

सोचने और सवालों के घेरे में खड़ा करने की अपील की।

मंच पर दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रकने के दृष्टिकों से दृष्टिकोण से एकल अभिनय चुनौती भरा होता है, चूंकि इसमें एक ही पात्र को कहानी को आगे बढ़ाना होता है। एकल अभिनय निभाने वाले किरदार को न केवल अभिनय के साथ लंबे संवाद बोलने पड़ते हैं बल्कि अभिनय को कहानी के साथ–साथ बदलते मनोभावों के साथ प्रस्तुत करना होता है। इस नाटक की एकल अभिनय के रूप में भावपूर्ण प्रस्तुति फ्लोरा बोस ने की थी। उन्होंने मंच पर धीरेंडू मजूमदार की माँ के अंतरंग द्वंद्वों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। जया मेहता के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक में उनकी सुलझी राजनीतिक और कलात्मक समझ की छाप स्पष्ट दिखाई दी।

दर्शकों से ठसाठस भरे हाल में दर्शकों ने नाटक की प्रस्तुति के बाद नाटक पर हुई चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई जो कि नाटक के सफल प्रस्तुति का निशान है।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैजः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़्बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

रंगमंच दिवस पर आगरा में विचार गोष्ठी

आगरा, 27 मार्च 2023: विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा), आगरा द्वारा जन नाट्य केंद्र मदिया कटरा आगरा पर किया गया।

गोष्ठी की अध्यक्षता रमेश पंडित ने की वक्ता पूरन सिंह ने अपने विचार रखे।

इप्टा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव व आगरा इप्टा के मुख्य निर्देशक दिलीप रघुवंशी ने विचार गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए कहा कि सभी कलाओ में नाट्य कला सबसे मुश्किल कला है, एक बड़े समूह के सहयोग द्वारा ही नाट्य प्रदर्शन संभव हो पाता है।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. ज्योत्स्ना रघुवंशी ने सर्वप्रथम डालटनगंज झारखंड में संपन्न इप्टा के 15वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे डॉक्टर ज्योत्सना रघुवंशी ने रंगमंच की समाज में

भागीदारी पर चर्चा करते हुए कहा कि कलाकार को मानवतावादी और संवेदनशील होना चाहिए।

इस अवसर पर आगरा इप्टा के असलम खान ने विश्व रंगमंच का इतिहास प्रस्तुत किया। दूसरे साथी जयकुमार ने मिस्र की अभिनेत्री समीहा अयूब का इस अवसर पर भेजा गया संदेश पढ़कर सुनाया।

अंत में इप्टा आगरा के कलाकारों द्वारा नाट्य पितामह राजेंद्र रघुवंशी रचित गीत, 'बाधक हो तूफान, बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा' की दमदार प्रस्तुति दी गई। इस गीत ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। गीत गाने वाले कलाकारों में परमानंद शर्मा, असलम खान, आनंद बंसल, जय कुमार, ओमकार राठौर थे। कार्यक्रम का सफल संचालन आगरा के महासचिव दिलीप रघुवंशी ने किया।

इस अवसर पर डॉ. असीम आनंद, रामनाथ शर्मा, एम पी दीक्षित, शरद गुप्ता, प्रियंका मिश्रा, पार्थो सेन, सीमन्त साहू, कोमल सिंह, प्रमोद सारस्वत, धर्मजीत की गरिमामई उपस्थिति रही धन्यवाद ज्ञापन नीरज मिश्रा ने दिया।

वित्तीय संकट और इसके प्रभाव

पेज 4 से जारी...

को बेच देते हैं। बेचते समय, यह आरोप लगाया जाता है कि वे इन कागजों का अतिमूल्यांकन करते हैं और बैंक ;ण का बडा हिस्सा खुद हड़प जाते हैं। यह न केवल अनैतिक है बल्कि शेष समुदाय के लिए हानिकारक है। यहां अडानी का मामला ठीक बैठता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया है कि अडानी समूह की कंपनियों ने शेयरों के मूल्य को 85 प्रतिशत अधिक मूल्यांकित किया है। यदि यह सच है, तो हेरफेर और झूठलाने कि इस हद को 'खतरनाक' कहा जा सकता है। अगर अडानी का मामला अलग नहीं है (ऐसे हजारों मामले हैं), तो वही सवाल उठता है कि नियामक निकायों, अधिकारियों, स्वतंत्र निदेशकों आदि ने क्या किया है या क्या कर रहे हैं! इस आर्थिक व्यवस्था के चरित्र को समझते हुए सच्चाई है कि ये सभी पदाधिकारी विशाल अति–मूल्यांकन और जालसाजी को नियंत्रित नहीं कर सके। आय और संपत्ति की असमानताओं को बढ़ाना इस व्यवस्था का नतीजा है। शेयर बाजार में जालसाजी पर प्रकाश डालने के लिए, यदि नियामक संस्था के मुख्य पदाधिकारी दूसरों को बाजार के बारे में यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें हिमालय की पहाड़ियों से कुछ गुरुओं से बाजार के बारे में संकेत मिले हैं, तो क्या यह बेतुकी बात नहीं है?

पूंजी समर्थक आय और संपत्ति पर कर को बदलकर जन–समर्थक बनाने पर विचार किया जाएय वित्तीय धोखाधड़ी, कर्ज वसूली की मात्रा, और अन्य प्रासंगिक कारकों में बदलाव की मात्रा के हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाए।

बैंकों की लगातार असफलता और वित्तीय रूप से उन्हें बचाने की जरूरत यहाँ तक कि, उसी व्यवस्था में, पूंजीवाद के घोर समर्थक के विश्वास को भी कमजोर करती है।

भाकपा ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी...

पेज 12 से जारी...

नेताओं के साथ एकजुटता व्यक्त की और गिरफ्तारी की निंदा की।

जबकि नेता डॉ. बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्य विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, वहां तैनात भारी पुलिस ने रैली करने वालों पर हमला किया और उन्हें सड़कों से घसीटकर पुलिस वैन में डालना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों और रैली करने वालों के बीच धक्का–मुक्की भी हुई। कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया और इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। इस दृश्य को देखने वाले पैदल यात्री ताली बजा रहे थे क्योंकि वामपंथी नेता बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे थे।

रामकृष्णा ने आगे संबोधित करते हुए मांग की है कि सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि यह शासनादेश क्यों लाया गया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कई बार हालांकि सरकार लिखित में भी हरी झंडी दे देती है, पुलिस गिरफ्तारी और हाउस अरेस्ट द्वारा दमनकारी उपायों का सहारा ले रही है। उन्होंने पदयात्राओं और धरनों को अनुमति नहीं दिए जाने पर भी रोष व्यक्त किया। गन्नवरम में धरना दे रहे शिक्षकों को अनुमति नहीं दी गई। सरकार शांतिपूर्ण तरीके से भी लोगों की समस्याओं को सामने नहीं आने दे रही है। चीफ जस्टिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय सीजे

को सु मोटो के जरिये मीडिया समाचार प्राप्त करके कार्रवाई करनी चाहिए। हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में लोगों ने इस तानाशाही सरकार को उचित सबक सिखाया है। लोग वाईएसआरसीपी को अपने–अपने घरों में वापस भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राज्य विधानसभा में जनप्रतिनिधियों पर अमानवीय और बैटबॉय हमले की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ विधायकों पर ही नहीं लोकतंत्र पर भी हमला है।

विधानसभा के पास यानी मंधाडम में अलग से एक प्रदर्शन भाकपा राज्य सचिवमंडल सदस्य जे अजयकुमार के नेतृत्व में हुआ।

इस बीच, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ. के नारायण ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए, लोकतंत्र के स्थान माने जाने वाली राज्य विधानसभा में टीडीपी विधायकों पर हमले की भी कड़ी निंदा की। हमले के मद्देनजर वाईएसआरसीपी के विधायकों को निलंबित करने के बजाय, टीडीपी विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया। नारायण ने वाईएसआरसीपी सरकार से सवाल किया कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक अमानवीय हैं या जानवर। यह वाईएसआरसीपी सरकार की हताशा की अभिव्यक्ति है जो हाल ही में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में हार गई। हालांकि वाईएसआरसीपी सरकार ने कई निरक्षरों को नामांकित किया है और जो इन निर्वाचन क्षेत्रों में स्नातक नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन चुनावों में वे हार गए। यह भविष्य के चुनावों के लिए भी संकेत है। इसलिए सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं पर हमले का सहारा ले रहा है। यहां तक कि विधानसभा में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं है और जिसने सरकार का विरोध किया है, उस पर हमला करना, फिर विधानसभा क्यों? वाईएसआरसीपी सड़क पर लड़ाई का विकल्प चुन सकती है। हालाँकि नारायणा ने राज्य सरकार से शासनादेश–1 को वापस लेने और इस तरह के बर्बर तरीकों को छोड़ने की मांग की।

मोदी के शासन से लोकतंत्र और ...

पेज 12 से जारी...

पर केसीआर सभी दलों के साथ केंद्र के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि इसके लागू होने तक किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि भाकपा की अनुभवी सांसद स्वर्गीय गीता मुखर्जी ने सभी विधायी निकायों में महिला आरक्षण के लिए संसद के अंदर और बाहर लड़ाई लड़ी थी। इसलिए वह विशेष बिल सीपीआई से जुड़ा है। नारायणा ने सवाल किया कि अगर केसीआर आश्रयहीनों को डबल बेड रूम के घर बांटते हैं तो वे झोपड़ी क्यों बनाते हैं? हालांकि केसीआर भाजपा के साथ मित्रवत थे, लेकिन अब वे भाजपा से खतरे को समझ गए हैं। सीपीआई ने तेलंगाना के साथ हुए अन्याय को महसूस करते हुए खुले तौर पर एलान किया और केसीआर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अलग तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी। तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के बाद से ही सीपीआई भूमि संघर्ष जारी रखे हुए है। महबूबाबाद क्षेत्र का जमींदारों को परास्त करने का इतिहास रहा है।

नारायणा ने केन्द्र सरकार से सवाल किया कि क्यों आदलतह आदेश के 24 घण्टे के अंदर ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई? ऐसे ही अपराधिक मामले 24 केन्द्रीय मंत्रियों के खिलाफ हैं क्यों नहीं उनकी भी सदस्यता इसी प्रकार खत्म घोषित कर दी गई। एक लोकतांत्रिक देश में भाजपा की ऐसी साजिशों का जवाब देश की जनता देगी।

अगर कोई बीजेपी की जय–जयकार करता है तो कोर्ट से सुरक्षित अपने घरो को जा सकता है और अगर जनविरोधी नीतियों का विरोध करता है तो उसे जेल भेजा जाता है। मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति अडानी को सौंप रही है। शुरुआत में बैंकों ने अडानी को कर्ज देने में आनाकानी की, लेकिन अब बैंक कर्ज के रूप में हजारों करोड़ रुपये अडानी को दे रहे हैं, जो बैड लोन बन गए हैं। अडानी से मोदी और अमित शाह को इतना लगाव क्यों? नारायण ने जोर देकर कहा कि जिसने भी बैंकों से भारी मात्रा में कर्ज लिया है, वह कोई और नहीं बल्कि गुजरात गैंग है। भाजपा सत्ता में आने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कमजोर कर रही है। बयाराम स्टील की गुणवत्ता अच्छी है लेकिन इसे निजी कंपनियों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार इसे खराब गुणवत्ता वाला स्टील बता रही है।

लाल शर्ट वाले भाकपा कार्यकर्ताओं की यह पदयात्रा भाकपा के राज्य सचिवमंडल सदस्य टी श्रीनिवास के नेतृत्व में 25 मार्च को कुरवी मंडल से शुरू हुई और इसका समापन एक विशाल रैली के साथ हनमकोंडा शहर में 5 अप्रैल 2023 को होगा। इस विशाल रैली की अध्यक्षता भाकपा महासचिव डी राजा द्वारा की जायेगी।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 2 – 8 अप्रैल, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 31.3.2023

स्कीम वर्करों का संसद मार्च

नई दिल्ली: देशभर से आये हजारों स्कीम वर्करों ने जंतर–मंतर पर वर्कर का दर्जा देने हेतु हुंकार भरी एआईटीयूसी से सम्बद्ध देश के सभी राज्यों यथा महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सहित लगभग अधिकांश राज्यों की आंगनवाड़ी सेविका–सहायिका यूनियनें, स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों, स्वास्थ्य देखभाल में वैश्विक स्तर पर कोरोना काल में चर्चित हुई आशा वर्कर्स सहित अन्य सरकारी स्कीमों में काम करने वाले हजारों स्कीम वर्करों ने एटक के फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर 28 मार्च को संसद मार्च कर हुंकार भरी। उन्होंने नियमित वर्कर का दर्जा देने के लिए भारतीय श्रम संसद–'इंडियन लेबर कांफ्रेंस' की अनुशंसा स्वीकार कर उन्हें श्रम कानूनों एवं श्रम अधिकारों से आच्छदित करने, मानदेय के बदले सरकारी कर्मचारियों की तरह 24000 रूपये वेतन और सुविधा देने सहित सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों यथा पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई, प्रसवकालीन छुट्टी सहित सारी सुविधाएं देने एवं सेवा नियमित करने के लिए फैसलाकून संघर्ष का शंखनाद किया।

इस प्रदर्शन एवं मार्च का नेतृत्व स्कीम वर्कर्स की फैडरेशनों की नेता माधुरी क्षीर सागर, एटक सचिव एवं स्कीम वर्कर्स नेत्री बबली रावत, श्याम काले, बिजय जेना, कुमार बिन्देश्वर सिंह, विभा पांडेय, सोनिया देवी, विनोदनी सहित एटक केंद्र से एटक महासचिव अमरजीत कौर, एटक कार्यकारी अध्यक्ष सांसद बिनॉय विश्वम, एटक उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरि, एटक सचिव सुकुमार दामले, वाहिदा निजाम आदि कर रहे थे। इस प्रदर्शन की तैयारी एवं प्रदर्शनकारियों के ठहराव आदि की व्यवस्था में श्याम काले के साथ दिल्ली राज्य एटक के कार्यकारी अध्यक्ष रामराज, महासचिव सतीश कुमार, बबन कुमार, विनोद कुमार एवं संजीव राणा सहित राज्य नेतृत्व के साथियों ने अहम भूमिका निभाई।

संसद मार्च के बाद जंतर–मंतर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एटक महासचिव अमरजीत कौर ने भारत सरकार के मजदूर विरोधी, किसान तथा जन विरोधी एवं देश विरोधी नीतियों की विषद् चर्चा करते हुए केंद्रीय श्रम संघों द्वारा घोषित 2023 को संघर्ष वर्ष के रूप में आयोजित करने के आह्वान को सफल बनाने एवं मोदी शासन के कुकृत्यों को जन–जन तक पहुंचाने हेतु जन–जागरण अभियान के बाद 9 अगस्त को सभी राज्यों में महापड़ाव आयोजित करने एवं 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के अभियान में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार द्वारा विरोध की आवाज को दबाने के लिए की जा रही बर्बर दमनात्मक एवं नीचतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हुए देश में चलाये जा रहे कारपोरेट गठजोड़ से लूट एवं भ्रष्ट अड़ानी–मोदी गठजोड़ को उजागर करने वाले हिंडनबर्ग रिपोर्ट की संसदीय समिति से जांच कराने के विपक्ष के सांसदों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने जनतंत्र संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी पर नृशंस हमलों की निंदा करते हुए सरकारी संस्थाएं ईडी, सीबीआई आदि के नीचतापूर्ण दुरूपयोग एवं न्यायपालिका में पहुंचाए गये अपने विचारवाले लोगों से विपक्ष पर हमला कराये जाने की निंदा की एवं आम जनता में इसे ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने जम्मू–कश्मीर में ठग कांति पटेल जिसकी पहुंच के साक्ष्य प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री तक के साक्ष्य हैं उस जेड श्रेणी सुरक्षा में कई महीनों तक जम्मू–कश्मीर सीमा क्षेत्र के सैन्य वेशों में पहुंच बनाने को असाधारण रक्षा चूक बताते हुए इसे राष्ट्रघाती कारवाई बताया जिसे मीडिया द्वारा दबा दिया गया है।

उन्होंने स्कीम वर्कर्स जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं के मांगों का समर्थन करते हुए उनके साथ हो रहे गलत व्यवहारों की निंदा करते हुए उनके आंदोलन के प्रति एटक की एकजुटता प्रदर्शित की। सभा को अनेकों नेताओं ने संबोधित किया जिसमें सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष एटक बिनॉय विश्वम, के. सुब्बारायन सांसद एवं उपाध्यक्ष एटक, पी. संतोषकुमार एमपी (भाकपा), एम. शनमुगम एमपी (डीएमके) एवं महासचिव एलपीएफ, पी आर नटराजन एमपी (सीपीएम), संजय देवरे–सांसद शिवसेना सहित अन्य सांसदों और ट्रेड यूनियन नेताओं सहित स्कीम वर्कर्स नेतृत्व के साथी माधुरी क्षीरसागर, शाम काले, बबली रावत, उषा सहनी, विजय जेना, विभा पांडे, गायत्री बाजपेयी, सोनिया देवी, विनोदनी, कुमार बिन्देश्वर, सहित विभिन्न राज्यों के अन्य नेता शामिल थे। प्रदर्शन एवं आम सभा के बाद एक प्रतिनिधिमंडल एटक उपाध्यक्ष एवं सांसद सुब्बारायन के साथ वाहिदा निजाम, शाम काले, माधुरी क्षीरसागर, बबली रावत आदि ने महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिक्षा मंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा जिसमें स्कीम वर्कर को वर्कर का दर्जा देकर सारी सुविधा देने सहित अन्य मांगें शामिल हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.